RNI No. DELMUL/2012/47011

20 सितंबर, 2026 रविवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 171

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

वैभव सूर्यवंशी बनेगा क्रिकेट का अगला स्टार : श्रीकांत 07

संक्षिप्त वार्ता

भारत जी-20 का इकलौता देश, जलवायु प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा किया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया, जहाँ उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का मोबाइल एप लांच किया। इस मौके पर, प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वपूर्ण घोषणा कर कहा कि भारत जी-20 देशों में एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसने पेरिस में हुए कोप-21 शिखर सम्मेलन में किए अपने सभी जलवायु प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी अक्सर गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन आज भी वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के कई देश इस चुनौती का सामना कर रहे हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग केस: सीएम सोरेन पीएमएलए कोर्ट में नहीं हुए पेश

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता ने अदालत में को बताया कि मुख्यमंत्री पूर्वनिर्धारित संवैधानिक दायित्वों में व्यस्त हैं। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख तय कर उन्हें शाम चार बजे व्यक्तिगत या वर्चुअल माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया है।

विद्यार्थियों के सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने को सरकार है संकल्पित: मुख्यमंत्री

प्रदेश में शिक्षा का बजट बढ़कर हुआ 38 हजार करोड़ रुपये

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विद्यार्थियों की मेहनत और उपलब्धियों को पुरस्कृत करना परिवार , समाज और सरकार का दायित्व है। विद्यार्थियों के सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। आर्थिक कठिनाइयों अथवा संसाधनों की कमी के कारण किसी भी प्रतिभावान विद्यार्थी की प्रगति नहीं रुकनी चाहिए। मेधावी विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही स्कूटी केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा और परिश्रम के पुरस्कार के साथ आत्मविश्वास और उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रोत्साहन है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव भोपाल के सुभाष स्कूल में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा-12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री स्कूटी योजना अंतर्गत स्कूटी वितरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को कक्षा 12 वीं में प्रथम प्रयास में ही 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक के साथ स्कूल में प्रथम स्थान पर आना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा शनिवार को समारोहपूर्वक प्रदेश के 7400 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी वितरित की गई।

कक्षा की सफलता से कैरियर के सपनों तक, विद्यार्थियों को सतत प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री स्कूटी योजना उन विद्यार्थियों के परिश्रम और प्रतिभा का सम्मान है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अध्ययन कर के बीच अपने परिवार और समाज को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विद्यार्थियों को नि:शुल्क किताबें, गणवेश और साइकिलें भी उपलब्ध करा रही है, ताकि आर्थिक परिस्थितियां उनकी पढ़ाई में बाधा न बनें। आज प्रदेश के बच्चे पढ़-लिखकर पारंपरिक व्यवसायों और खेती-किसानी में भी नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। कई विद्यार्थी एग्रीकल्चर स्टार्ट-अप शुरू कर परिवार की आय बढ़ाने का सपना देख रहे हैं। आधुनिक तकनीक और नवाचार से कृषि को लाभ का बेहतर माध्यम बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और भविष्य के प्रति उनकी स्पष्ट सोच की सराहना करते हुए कहा , हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि किसान और सामान्य परिवारों से आने वाले विद्यार्थी भी आज चार्टर्ड एकाउंटेंट, चिकित्सक, अधिवक्ता, कृषि वैज्ञानिक और उद्यमी बनने के सपने देख रहे हैं। विद्यार्थियों की यह सोच नए और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की पहचान है। देश और प्रदेश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने के साथ उन्हें साकार करने के लिए परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

बेटियों को स्कूटी मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बेटियों को शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर मिलने से केवल उनका जीवन नहीं बदलता, बल्कि पूरे परिवार और समाज का वातावरण सकारात्मक बनता है। मेधावी बेटियों को स्कूटी मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उच्च शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने की राह अधिक सुगम होगी। राज्य सरकार विद्यार्थियों को न्यूनतम आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर और समर्थ बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता सुधार के लिए बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। आजादी के बाद 1956 में मध्यप्रदेश की स्थापना हुई। राज्य का कुल बजट 55 साल में केवल 22 हजार करोड़ रुपए था और वर्ष 2002-03 तक स्कूल शिक्षा विभाग का बजट मात्र 2600 करोड़ रुपए था। हमारी सरकार ने वर्ष 2025-26 में कुल 4 लाख 38 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया , इसमें स्कूल शिक्षा के लिए 38 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह वृद्धि बताती है कि राज्य सरकार शिक्षा, विद्यार्थियों और प्रदेश के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर काम कर रही है।

सांदीपनि विद्यालय सुविधाओं और पढ़ाई में निजी स्कूलों को पीछे छोड़ रहें हैं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 2002-03 तक प्राथमिक स्कूलों में ड्रॉप आउट दर 16 प्रतिशत थी, जो वर्तमान में शून्य हो चुकी है। प्रदेश में सर्वसुविधायुक्त सांदीपनि विद्यालय खोले जा रहे हैं, जो सुविधाओं और पढ़ाई के मामले में निजी स्कूलों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इन विद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। अब बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट लिस्ट में 50 प्रतिशत विद्यार्थी सांदीपनि और शासकीय स्कूलों से आ रहे हैं। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना और उन्हें उनकी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ने के अवसर देना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कठिनाई के दौर से निकले और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हम सबने 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री श्री मोदी का ऐतिहासिक जन्मोत्सव मनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में जनधन खातों, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), डिजिटल भुगतान व्यवस्था और कोविड-19 टीकाकरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं की सहायता सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

एअर इंडिया एक्सप्रेस के 8 क्रू सस्पेंड

नई दिल्ली। एअर इंडिया एक्सप्रेस ने दुबई-अमृतसर फ्लाइट के 8 क्रू मेंबर्स को सस्पेंड किया है। इनमें चार पायलट शामिल हैं। यह कार्रवाई अनिवार्य पोस्ट-फ्लाइट ब्रीथ एनालाइजर (अल्कोहल) टेस्ट में देरी पर हुई। मामला 2 अगस्त की दुबई-अमृतसर फ्लाइट का है। क्रू को अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद 2 घंटे में ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट कराना था, लेकिन उन्होंने यह टेस्ट 2 घंटे 35 मिनट बाद कराया। एयरलाइन ने मामले की जानकारी एविएशन सेफ्टी बॉडी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) को दी और सभी 8 सदस्यों को ड्यूटी से हटा दिया। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब हाल ही में एअर इंडिया के एक पायलट का साइकोएक्टिव पदार्थ का टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसके बाद एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस के पायलटों के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य किया गया।

तिरुपति लड्डू घी में मिलावट: ईडी ने प्रमोटर को दबोचा

तिरुपति। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि वर्ष 2019 से 2024 के बीच तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को जिस घी की आपूर्ति की गई, उसमें कथित तौर पर शुद्ध गाय के घी के बजाय रिफाइंड पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल और पामोलीन जैसे वनस्पति तेलों का इस्तेमाल किया गया। एजेंसी के अनुसार, इन पदार्थों को घी जैसा रूप और गुण देने के लिए कुछ रसायनों का भी इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। ईडी ने इस अवधि में करीब 230 करोड़ रुपये की कथित संदिग्ध आपूर्ति की बात कही है।

मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सुकृति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक कैलाश चंद मंगला को गिरफ्तार किया है। एजेंसी का आरोप है कि उनकी कंपनी से करीब 96 करोड़ रुपये मूल्य का कथित मिलावटी घी तैयार कर आपूर्ति किया गया। जांच के दौरान एजेंसी ने एमजी-90, मोनोग्लिसराइड्स, मायवेसिट सॉफ्ट 400 और एसीटिक एसिड एस्टर जैसे रसायनों के इस्तेमाल का भी दावा किया है। आरोप है कि वनस्पति तेलों में इन पदार्थों को मिलाकर ऐसा मिश्रण तैयार किया गया, जिसे घी के रूप में आपूर्ति किया जा सके। तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद का धार्मिक और भावनात्मक महत्व बेहद व्यापक है। देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने साथ भी ले जाते हैं। ऐसे में प्रसाद में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सामने आया कोई भी सवाल श्रद्धालुओं की आस्था के साथ-साथ खाद्य गुणवत्ता और आपूर्ति व्यवस्था पर भी असर डालता है। प्रवर्तन निदेशालय अब यह पता लगाने में जुटा है कि कथित मिलावटी घी का उत्पादन किस स्तर पर हुआ, इसकी आपूर्ति किस माध्यम से की गई और पूरी प्रक्रिया में कौन-कौन लोग शामिल थे। जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इतनी बड़ी मात्रा में कथित रूप से मिलावटी उत्पाद की आपूर्ति के दौरान गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया में इसे पकड़ा क्यों नहीं गया। कैलाश चंद मंगला की गिरफ्तारी के बाद मामले में जांच तेज होने की संभावना है। एजेंसी कंपनी से जुड़े दस्तावेजों, उत्पादन प्रक्रिया, खरीद और आपूर्ति से संबंधित रिकॉर्ड तथा भुगतान के विवरण की पड़ताल कर रही है।

नाबालिग से दुष्कर्म : प्रियंका बोलीं- जिम्मेदारी लेने से बच रही सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में महिला सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में इस क्रूर घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक 17 साल की बच्ची के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई और उसे बर्बरता से मार डाला गया। उन्होंने याद दिलाया कि कुछ ही दिन पहले एक और नाबालिग लड़की का बलात्कार किया गया था।

प्रियंका गांधी ने महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खोखली बातें होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सैकड़ों महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा होती है, लेकिन अपराधी ठोस कार्रवाई की उम्मीद नहीं कर सकते, यहां तक कि एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। उन्होंने समाज और सरकार दोनों को महिलाओं को सुरक्षा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देने में पूरी तरह विफल करार दिया। इससे पहले, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी दिल्ली की घटना पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, दिल्ली में 17 साल की युवती के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या कर शव खुले मैदान में फेंक दिया गया। राजधानी में इतनी बड़ी दरिंदगी और पुलिस को कई दिनों तक भनक नहीं लगती। दुर्भाग्य है कि दिल्ली आज राजधानी नहीं, महिलाओं के लिए हर दिन की खौफनाक कहानी बनकर रह गई है।

बिपाशा के प्रोटीन पाउडर में कीड़े मिलने का दावा: कंपनी ने दी सफाई

मुंबई। अभिनेत्री बिपाशा बसु ने हाल ही में अपने प्रोटीन पाउडर को लेकर एक दावा किया, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। 10 सितंबर को बिपाशा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने नए खोले गए आइसोप्योर प्रोटीन पाउडर के कंटेनर में छोटे-छोटे कीड़े जैसे कुछ दिखाई देने की बात कही। अभिनेत्री ने इस मामले में महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) कमिश्नर तुकाराम मुंढे से भी मदद की अपील की थी। अब न्यूट्रिशन ब्रांड ने इस मामले पर अपनी सफाई दी है। ग्लेनबिया परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन (जीपीएन) इंडिया के जनरल मैनेजर सुमित माथुर ने बताया कि उन्होंने बिपाशा बसु से तुरंत

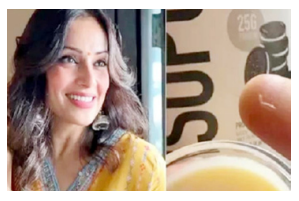

संपर्क किया है। आइसोप्योर की टीम अब उस प्रोटीन पाउडर के पैक की जांच कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि टीम यह पता लगाएगी कि पैक असली है या नहीं और प्रोडक्ट की गुणवत्ता कैसी है। कंपनी ने कहा कि ग्राहकों की सुरक्षा और प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी अपने अधिकारियों के साथ मिलकर नकली प्रोडक्ट्स पर नजर रखती है। आइसोप्योर ने ग्राहकों से अपील की है कि वे प्रोडक्ट केवल अधिकृत दुकानों या वेबसाइट से ही खरीदें। इस्तेमाल करने से पहले पैक पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी प्रोडक्ट के असली होने की जांच कर लें। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब महाराष्ट्र एफडीए खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर बड़े स्तर पर जांच अभियान चला रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जून से अगस्त 2026 के बीच एफडीए ने 37,604 सैंपल इकट्ठे किए, जिनमें से 34,584 खाद्य सैंपल थे। विभाग ने इस दौरान 32,604 सैंपल की जांच की। वहीं, 100 दिनों में लगभग 12,000 खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण की जानकारी भी सामने आई है।

ममता के दखल के बाद चौधरी का यू-टर्न- वापस लिया चुनाव से हटने का फैसला

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने चुनाव से हटने की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही अपना फैसला बदल दिया। शनिवार को चौधरी ने कहा कि वह उपचुनाव लड़ना जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहने पर अपना फैसला वापस लिया है। चौधरी ने इससे पहले नए चुनाव चिन्हे के साथ चुनाव लड़ने में परेशानी होने के साथ ही राज्य प्रशासन पर पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया और चुनाव से हटने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि कार्यकर्ताओं को प्रचार करने से रोका जा रहा है और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उनके चुनाव से हटने की खबर सामने आई थी।

तमिलनाडु में स्कूली बच्चों को खाने में मिलेगी चिकन बिरयानी

सीएम विजय 22 को पेरुंथलैवर कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम के विस्तार की करेंगे शुरूआत

चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय 22 सितंबर को छठी से आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए पेरुंथलैवर कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम के विस्तार की शुरूआत करेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ए राजमोहन ने बताया कि सीएम विजय ने सामान्य खाने के अलावा अलग-अलग तरह के और स्वादिष्ट मेन्यू विकल्प लाने के लिए एक विशेष समिति बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने मेन्यू में नए बदलावों का संकेत देते हुए चिकन बिरयानी जैसे नॉन-वेज विकल्प शामिल करने की बात भी कही है।

इस विस्तारित योजना से 15,454 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में छठी से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 15.30 लाख अतिरिक्त छात्रों को लाभ मिलेगा। यह छात्रों के पोषण के लिए एक अहम कदम है, जिससे यह तय होगा कि वे अपने दिन की शुरूआत सेहतमंद तरीके से करें। इस विस्तार के लिए चालू वित्त वर्ष में 217.63 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड आवंटित किया गया है, जिससे इस कार्यक्रम का कुल बजट बढ़कर 724 करोड़ रुपए हो गया है। 22 सितंबर को विस्तारित योजना शुरू करने का फैसला यहां सचिवालय में विजय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया।

उम्मीद है कि सीएम यहां तिरुवनमियूर

के एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में इस पहल की शुरूआत करेंगे। इस योजना को 17 सितंबर को शुरू होना था, लेकिन सीएम विजय की लंदन यात्रा के कारण इसे टाल दिया गया था। इसे चेंगलपट्टू और तिरुप्पुर जिलों में लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां क्रमश: मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता लागू है। मेन्यू में उपमा, खिचड़ी और पोंगल जैसे पौष्टिक मुख्य व्यंजन शामिल हैं, साथ ही हफ्ते में दो बार मोटे अनाज से बने विकल्प भी दिए जाएंगे।

वहीं, तमिलनाडु महिला विकास निगम ग्रामीण इलाकों, टाउनशिप इलाकों और उनसे सटे ग्रामीण इलाकों के 12,857 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में यह प्रोग्राम चलाएगा। रिलीज में कहा गया, नाश्ता संबंधित स्कूलों में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा तैयार और परोसा जाएगा। इस योजना का विस्तार छात्रों के स्वास्थ्य, पोषण, स्कूल में उपस्थिति और सीखने की क्षमता जैसे पहलुओं को जोड़कर स्कूली शिक्षा की नींव को और मजबूत करने के लिए किया जा रहा है।

...और सघन जांच की जरूरत होगी

रिपोर्ट के मुताबिक राजमोहन ने कहा कि लंबे समय के लक्ष्य के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट और साफ-सफाई के कड़े मानकों के आधार पर छात्रों को चिकन बिरयानी जैसे नॉन-वेज विकल्प देने पर विचार किया जाएगा। इस बारे में विस्तार से पूछे जाने पर राजमोहन ने कहा कि पूरे सम्मान के साथ कहता हूं, जेल में बंद कैदी को भी चिकन बिरयानी खाने को मिलती है। तो मेरे स्कूलों के बच्चे चिकन बिरयानी क्यों नहीं खा सकते? हालांकि, मंत्री ने साफ किया कि इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकता। भविष्य में स्कूली बच्चों को इसे देने से पहले, साफ-सफाई के कड़े मानकों को पूरा करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट और सघन जांच की जरूरत होगी।

ग्रेटर नोएडा में हिट एंड रन: छात्रों को टक्कर मारकर भागी तेज रफ्तार कार, 5 घायल

हादसे का वीडियो वायरल, कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां तेज रफ्तार कार ने सड़क से गुजर रहे छात्रों को एक के बाद एक टक्कर मार दी। हादसे में करीब चार से पांच छात्र घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी चालक कार समेत मौके से फरार हो गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, छात्र सड़क से गुजर रहे थे। इसी दौरान

तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर उनकी तरफ आ गई और कई छात्रों को टक्कर मार दी। अचानक हुई टक्कर से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में घायल छात्रों को आसपास मौजूद लोगों ने मदद पहुंचाई और उपचार के लिए अस्पताल भेजने की व्यवस्था की।

हादसे के बाद चालक ने कार रोककर घायलों की मदद करने के बजाय वाहन को लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस अब कार के नंबर और चालक की पहचान करने में जुटी है। प्रत्यक्षदर्शियों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है।

हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो को जांच में शामिल करते हुए घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। फुटेज के आधार पर कार और चालक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस वाहन को बरामद करने के साथ चालक को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है।

जज का बड़ा फैसला

सेवानिवृत्ति पर देह के साथ 1 करोड़ दान करेंगे

जबलपुर। तन मन धन सौंपना केवल कहावत थी, लेकिन मप्र के एक जज ने इसे हकीकत में बदल दिया। उन्होंने दान में न केवल एक करोड़ देने का संकल्प लिया बल्कि खुद की देह भी दान करने की घोषणा कर दी। मतलब तन मन और धन सब कुछ दान कर दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने अपनी सेवानिवृत्ति के अवसर पर दो बड़े और प्रेरक फैसलों की घोषणा की है। उन्होंने अपने जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) से मिलने वाली पूरी रकम, जो करीब 1 करोड़ रुपये बताई गई है, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में दान करने का संकल्प लिया है। अलग-अलग रिपोर्टों में जीपीएफ की अनुमानित रकम 1.01 करोड़ से 1.1 करोड़ रुपये बताई गई है। जस्टिस सिंह ने 17 सितंबर को अपने विदाई समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि जीपीएफ की राशि जैसे ही उन्हें प्राप्त होगी, वह पूरी रकम राष्ट्र निर्माण के लिए पीएम केयर्स फंड को देने का संकल्प लेते हैं।

संपादकीय

देश में मोदी होना

प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की विलंबित बधाइयां...। हम उनके बेहतर स्वास्थ्य, सतत सक्रियता और दीर्घायु की दुआएं भी करते हैं। मोदी सवा 12 साल, अर्थात 4500 से अधिक दिन, से भारत के निरंतर प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, जो लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बने हैं। यह हमारे सशक्त और विवेकी लोकतंत्र तथा न्यायिक जनमत की ही ताकत है। 1984-85 के लोकसभा चुनाव में जिस भाजपा के मात्र दो सांसद जीत पाए थे, राष्ट्रीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी को पराजित होना पड़ा था, वह मई 2014 से निरंतर केंद्रीय सत्ता में है। लोकसभा में भाजपा के आज 240 सांसद हैं, 282 और 303 सांसद भी रह चुके हैं। राज्यसभा में 116 सांसद हैं और एनडीए के सांसदों को मिला कर पूर्ण बहुमत है। देश में पार्टी के कुल 1813 विधायक हैं। भाजपा-एनडीए की 22 राज्यों में सरकारें हैं और देश की करीब 78 फीसदी आबादी पर उनका शासन है। ये तथ्य आप भी जानते होंगे। हम तो प्रसंगवश प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की चौतरफा स्वीकृति का दस्तावेजी यथार्थ है। बीते 12 साल का कालखंड प्रधानमंत्री मोदी का रहा है। उनके नेतृत्व में सभी पूर्वोत्तर राज्य भाजपामय हैं, जो कभी कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों के गढ़ थे। ओडिशा जैसे पटनायकवादी और गैर-भाजपा राज्य में आज भाजपा का मुख्यमंत्री है। वाममोर्चे और ममता बनर्जी के जनाधार वाला राज्य, जहां कई क्षेत्र मुस्लिम-बहुल हैं, लिहाजा भाजपा-विरोधी हैं, उस पश्चिम बंगाल में 202 सीटों का ऐतिहासिक, प्रचंड जनादेश आज भाजपा के पक्ष में है। बेशक दक्षिण भारत अभी भाजपामय होना शेष है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अपरंपरागत नेता हैं। भारत गुटनिरपेक्ष, समाजवादी राजनीति और कूटनीति के झंडाबरदार देशों में लंबे समय तक रहा। कमोबेश इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल तक इसी सोच और कूटनीति का प्रचार किया जाता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बहुध्रुवीय, बहुगठबंधन राजनीति की सोच दी, लिहाजा कूटनीति भी बदली। आज भारत के यूरोप, पश्चिमी देशों के साथ राजनयिक संबंध हैं, तो रूस और चीन के साथ भी भारत कई संगठनों, शिखर सम्मेलनों का सदस्य है। मुस्लिम-अरब बहुल के देश भी भारत के मित्र हैं। जी-20 में ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर अफ्रीकी देशों को शामिल करने के मेजबान प्रधानमंत्री मोदी के सफल प्रयास के मद्देनजर अफ्रीकी देश भारत को अपना अंतरंग हमदर्द मानते हैं। शायद कूटनीति की व्यापकता और विविधता के कारण ही 37 देश अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी और उनके जरिए भारत को विभूषित कर चुके हैं। यह भारतीय प्रधानमंत्री का विश्व-कीर्तिमान है।

प्रधानमंत्री मोदी की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग भी 68-71 फीसदी आंकी गई है, जो सर्वाधिक है। सभी विश्व नेताओं की औसत रेटिंग 50 फीसदी से कम है। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप तो रसातल में हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपरंपरागत इसलिए हैं कि उन्होंने लालकिले से 15 अगस्त के संबोधन में देवालय से पहले शौचालय को अहम करार दिया था और फिर यह राष्ट्रीय योजना बनाई थी। ऐसा कहने और करने वाले मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। आज देश में करीब 12 करोड़ पारिवारिक शौचालय हैं। यह बयान खुद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दे चुके हैं। अब शौचालय स्वच्छता के साथ-साथ सामाजिक, पारिवारिक और महिला की प्रतिष्ठा के प्रतीक बन चुके हैं। जन-धन खाता, मुद्रा योजना, उज्जवला योजना और 81 करोड़ से अधिक भारतीयों को मुफ्त राशन आदि सभी परंपरागत लीक से हट कर योजनाएं हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री के संदर्भ में एक राजनीतिक जुमला उछाला जाता रहा है-हामोदी है तो मुमकिन है। हमारा विश्लेषण यह मानता है-मोदी होना आसान नहीं प्रधानमंत्री मोदी भी इनसान हैं, लिहाजा उनमें भी मानवीय विरोधाभास और खामियां हैं। वह अतिमानव नहीं हैं और न ही ऐसा चरित्र-चित्रण करना चाहिए। भाजपा के शीर्षस्थ नेता रहे लालकृष्ण आडवाणी कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी सबसे अधिक आलोचित नेता हैं। हमारा मानना है कि यह आलोचना नफरत की हद तक है। लोकतंत्र में यह स्वीकार्य नहीं है, लिहाजा बार-बार चुनावी जनादेश नफरतबाजों के खिलाफ जाता है। हमने भी देश में स्कूल, शिक्षा, अध्यापक, बेरोजगारी, गरीबी, अर्थव्यवस्था, आर्थिक असमानता आदि को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल किए हैं। यही लोकतंत्र है, लिहाजा प्रधानमंत्री का लगातार विश्लेषण किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवाओं को रोजगार दिलाने में प्रभावी भूमिका निभानी होगी। यह भी सत्य है कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती। इसलिए निजी क्षेत्र को इस तरह विकसित करना होगा कि वहां युवाओं के लिए पर्याप्त संख्या में रोजगार पैदा हो। स्वरोजगार की दिशा में सरकार ने अनेक पग उठाए हैं, लेकिन बेरोजगारी की समस्या अभी पूरी तरह हल नहीं हो पाई है। इसलिए फोकस बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करने पर होना चाहिए।

खाने-पीने की राजनीति से भाजपा की तौबा

अधिकारी के वीडियो से प्रेरणा लेते हुए, सत्ताधारी पार्टी ने सुझाव दिया कि उसे शाकाहारी-मांसाहारी बहस को समाप्त कर देना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि यह विवाद यहीं समाप्त होना चाहिए। भाजपा ने खानपान को लोगों का व्यक्तिगत मामला बता कर मुख्यमंत्री अधिकारी के मछली खाने के विवाद से पीछा छुड़ाने की कोशिश की है। सवाल यह है कि क्या भाजपा लोगों को अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार देती है। लोग क्या खाएं, क्या पीएं, कैसे कपड़े पहनें और इससे बढ़कर किसके साथ रहें या किसके साथ नहीं रहें, क्या इन सभी मामलों में भाजपा की सहमति है। दरअसल भाजपा वोट बैंक के हिसाब से मुद्दे तय करती है। मतलब जहां वोट बैंक को खुश रखना है तो लोग मांस मछली खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किन्तु ऐसा करने से यदि विपक्षी दलों को निशाना बनाकर वोट बटोरे जा सकते हैं, तो भाजपा चूकेगी नहीं।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी के राजधानी कोलकाता स्थित सदियों पुराने कालीघाट मंदिर में मछली खाने का मुद्दा सुर्खियों में रहा। अधिकारी अमावस्या के अवसर पर कालीघाट गए, जिसे शाक्त हिंदू शुभ मानते हैं। उन्होंने जमीन पर बैठकर भोग खाया, जिसमें एक विशाल मछली का सिर शामिल था, जो कालीघाट भोग की थाली का प्रतीक है। इसके अलावा, तली हुई मछली और बसंती पुलाव (पीले चावल) भी थे। इससे पहले बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली हिंदुओं से मांसाहारी भोजन का त्याग करने की अपील की थी। उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन करने वाले बंगाली हिंदुओं को पाखंडी भी कहा था। शास्त्री ने कहा- ह्यमांसाहारी भोजन की बिक्री बंद करने के पक्ष में कौन है? कृपया अपने मोबाइल फोन की लाइट जलाकर यह संकेत दें। यह संदेश पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और सरकार को इस मुद्दे से अवगत कराया जाना चाहिए। दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल में मांस और शराब की दुकानें बंद रहनी चाहिए। इस पर भाजपा के बंगाल प्रमुख सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि बागेश्वर बाबा एक अलग ही दुनिया से आते हैं। बंगाल के लोग क्या खाएंगे, यह तय करने का बागेश्वर बाबा को कोई अधिकार नहीं है। बंगाली लोग मछली और मांस खाएंगे। विवेकानंद ने बंगालियों द्वारा मांस और मछली के सेवन के पक्ष में बात की है। उन्होंने बागेश्वर बाबा की अपील का जवाब देते हुए कहा कि वे स्वयं मंदिर गए और देवता को अर्पित किए गए प्रसाद में से मांसाहार का सेवन किया। बंगाली लोगों के नियमित आहार में मछली एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है। भारत के पूर्वी क्षेत्रों में सांस्कृतिक और धार्मिक रीति-रिवाजों के अंतसंबंध के कारण, इस क्षेत्र में प्रचलित शाक्त परंपराओं में मछली एक महत्वपूर्ण प्रसाद के रूप में उभर कर सामने आई है।

उदाहरण के तौर पर, कालीघाट में काली को मछली और बलि के लिए बकरी का मांस दोनों ही अर्पित किए जाते हैं। देश के इस हिस्से में सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा के दौरान भोजन मुख्य रूप से मांसाहारी होता है। इसे बुरा नहीं माना जाता, बल्कि इसका जश्न मनाया जाता है। कुछ परंपराओं में शाकाहारी भोजन के नियम कायम हैं, जबकि कुछ में अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में देवी-देवताओं को मांसाहारी भोजन अर्पित करना अनिवार्य है। हालांकि, इस तरह की प्रथाओं को सुदूर पश्चिम या उत्तर में इतने बड़े दर्शक वर्ग नहीं मिलते हैं, यही कारण है कि इस तरह की आहार संबंधी प्राथमिकताएं जिज्ञासा जगाती रहती हैं और बहस को जन्म देती हैं। भारत एक हिंदू बहुसंख्यक देश है और भारत में शाकाहार के मुकाबले नॉनवेज खाने वाले भी बहुसंख्यक हैं। अर्थात नॉनवेज खाने वालों की संख्या ज्यादा है। 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में 57 प्रतिशत पुरुष और 45 फीसदी महिलाएं नॉनवेज खाते हैं। ऐसे में सवाल उठाते हैं कि क्या किसी का मछली खाना राजनीतिक मुद्दा हो सकता है? क्या खाने की आदत से धर्म और इनसान पहचाना जाएगा? क्या हिंदू सिर्फ शाकाहारी होते हैं और जो नॉनवेज खा लेते हैं वो विधर्मी? अगर सावन या नवरात्रि में कोई नॉनवेज खाता है तो क्या गलत है? क्या सावन या नवरात्रि में नॉनवेज खाकर वीडियो बनाने या पोस्ट करने से दूसरों की भावना को चोट पहुंचती है और क्या सावन-नवरात्र में किसी के नॉनवेज खाने का वीडियो डालने से अल्पसंख्यक वोटर वोट दे देते हैं? दरअसल खानपान के मामले को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मुद्दा बना कर कई मौकों पर भुनाने का प्रयास किया है। विशेषकर विपक्षी दलों के नेताओं के ऐसे वीडियो को खूब प्रचारित किया गया, ताकि उन्हें नॉनवेज खाना वाला साबित करके शाकाहारी भोजन वाले मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 अप्रैल 2024 को जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मंच से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर त्योहारों के समय पर नॉनवेज खाने वाले वीडियो को लेकर जमकर हमला बोला था।

पीएम मोदी ने कहा था कि आरजेडी नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के त्योहारों के समय नॉनवेज खाने वाले वीडियो पर निशाना साधते हुए इनका नाम लिए बगैर कहा था कि सावन के महीने में एक सजायाफ्ता मुजरिम अर्थात लालू यादव के घर जाकर वो मटन बना रहे थे। ये लोग ऐसा जानबूझकर ऐसा करते हैं, ताकि देश की मान्यताओं पर हमला हो। उन्होंने कहा- कानून और मोदी किसी को कुछ भी खाने से नहीं रोकते हैं। सबको स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज और नॉनवेज खाएं। लेकिन इन लोगों की मंशा ऐसा वीडियो बनाकर देश के लोगों को चिढ़ाने की होती है। त्योहार के सीजन में मुख्यमंत्री अधिकारी के मछली का बड़ा सिर खाए जाने पर न तो भाजपा ने कोई आपत्ति की और न ही पीएम मोदी ने। मतलब तेजस्वी यादव, लालू यादव और राहुल गांधी ने नॉनवेज खाया तो पीएम मोदी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाते हुए एक तरह से हिन्दुओं की भावनाओं के खिलाफ करार दिया, किन्तु अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री ने अब जब मंदिर में जाकर मछली का सिर खाया तो भाजपा बचाव में उतर आई।

उत्तरी राज्यों से शाकाहारी खानपान की आदतों को मांसाहारी बंगाल में लाने के लिए अक्सर आलोचनाओं का सामना करने वाली भाजपा ने बार-बार ऐसे दावों को खारिज किया है। अधिकारी के वीडियो से प्रेरणा लेते हुए, सत्ताधारी पार्टी ने सुझाव दिया कि उसे शाकाहारी-मांसाहारी बहस को समाप्त कर देना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि यह विवाद यहीं समाप्त होना चाहिए। भाजपा ने खानपान को लोगों का व्यक्तिगत मामला बता कर मुख्यमंत्री अधिकारी के मछली खाने के विवाद से पीछा छुड़ाने की कोशिश की है। सवाल यह है कि क्या भाजपा लोगों को अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार देती है। लोग क्या खाएं, क्या पीएं, कैसे कपड़े पहनें और इससे बढ़कर किसके साथ रहें या किसके साथ नहीं रहें, क्या इन सभी मामलों में भाजपा की सहमति है। दरअसल भाजपा वोट बैंक के हिसाब से मुद्दे तय करती है। मतलब जहां वोट बैंक को खुश रखना है तो लोग मांस मछली खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किन्तु ऐसा करने से यदि विपक्षी दलों को निशाना बनाकर वोट बटोरे जा सकते हैं, तो भाजपा चूकेगी नहीं। पीएम मोदी का लोकसभा चुनाव के दौरान लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर किया गया तंज इसका उदाहरण है।

योगेंद्र योगी, स्वतंत्र लेखक

क्या भाजपा चीन के माओवाद से प्रभावित ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को दिमागी नक्सली को पहचान और उनसे मुक्ति पाने का जो आह्वान किया था, उसके बाद जो प्रतिक्रिया भाजपा के अंदर देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए बरबस ही माओवाद और हिटलर की यादें ताजा होने लगी हैं। भारत सरकार और गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले कुछ महीनो में बार-बार कहा है, कि भारत से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया से जो रील, विपक्षी पार्टियों, छात्रों और कांग्रेस के खिलाफ जारी हो रही हैं। जिस तरह के आक्रामक विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षियों से निपटने के लिए लाठी, तलवार और एके-47 राइफल का इस्तेमाल कर रही है, वह चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी में सोशल मीडिया की नई टीम बनी है। उसने कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के खिलाफ आक्रामक विज्ञापन की श्रृंखला जारी की है। यह सारे विज्ञापन भाजपा के प्रदेश हैंडल से भी जारी किए जा रहे हैं। इसमें तीन अलग-अलग दौर के हथियारों का उपयोग किया गया है। एक विज्ञापन में भाजपा की सारी प्रदेश इकाइयां लाठी के साथ कांग्रेस कार्यकताओं की धुनाई कर रही हैं। एक घेरा है जिसमें कांग्रेस बीच में खड़ी है, चारों तरफ से उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। दूसरे विज्ञापन की रील में रोम के गुलाम विद्रोह पर बनी फिल्म का दृश्य समाहित किया गया है, जिसमें सारे गुलाम योद्धा हाथ में तलवार लेकर हिंसक अंदाज में हमले के लिए तैयार दिख रहे हैं। तीसरे विज्ञापन में एके-47 और एके-56 राइफल हाथ में लेकर भाजपा समर्थक दिमागी नक्सलों पर हमला कर रही हैं।

भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया ने विपक्षी दलों के लिए जिस तरह की आक्रामकता विज्ञापनों में दिखाई है और भाजपा के प्रदेश हैंडिल से वह जारी हो रहे हैं। उसके बाद सारे देश में यह चर्चा होने लगी है, क्या भारतीय जनता पार्टी हिटलर और माओ के रास्ते पर चल पड़ी है? इन तीन विज्ञापनों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे विज्ञापन सोशल मीडिया हैंडल से जारी किए गए हैं। इनमें ताकत का प्रदर्शन करते हुए सामान्य नागरिकों और विपक्षी दलों के लिए नफरत का भाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। इन विज्ञापनों के जरिए केवल कांग्रेस या विपक्षी दलों को निशाने पर नहीं लिया गया है। इसमें छात्रों और युवाओं को भी निशाने पर लिया गया है। एक विज्ञापन में मिजार्पुर सीरीज के एक दृश्य का इस्तेमाल किया गया है। जिसमें एक सामान्य विद्यार्थी कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहता है। उसे खलनायक के गुंडे बेटे द्वारा जबरिया रोका जाता है। यह गुंडे का लड़का क्लास रूम में आकर छात्र की पिटाई करता है, वह कहता है, तुम क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो। भाजपा ने पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से नई विज्ञापन सीरीज जारी की है, उसमें मारकाट और ताकत के बल पर सत्ता करने का जो मनसूबा दिखाई दे रहा है, वह काफी डरावना और भयभीत करने वाला है। भाजपा ने राजनीतिक लड़ाई में जिस तरह से विज्ञापनों के जरिए संदेश प्रसारित करने के लिए हिंसा और अराजकता का रास्ता चुना है, वह भारतीय संदर्भ में आश्चर्यजनक है। भाजपा के सोशल मीडिया ने जिस तरह से सोनिया गांधी, अखिलेश यादव एवं और अन्य नेताओं के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक कंटेंट तैयार किए हैं, भारत की जनता उसे स्वीकार करेगी या नहीं, यह कहना भी बड़ा मुश्किल है।

भारत में इस तरह की नफरत और हिंसा वाले विज्ञापन, जो भाजपा हैंडल से सीरियल के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, उसने आम लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की मानसिकता का कोई स्थान नहीं है। अगले साल पांच राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। युवा नाराज होकर सड़कों पर हैं। सारे विपक्षी दल सड़कों पर आकर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा का सोशल मीडिया क्या करना चाहता है, भाजपा की मंशा क्या है, इसको लेकर अब आम आदमी में चिंता दिखने लगी है। भारत की संस्कृति इस तरह की नहीं है, जनता इस तरह से भय और दबाव में आकर कोई निर्णय लेगी? अंग्रेजों के शासन में जब भारत पूरा बंटा हुआ था। अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी ताकत थी। उसके बाद भी भारत के गरीब आदिवासी, दलित और सामान्य वर्ग के लोग सड़कों पर आकर लाठी डंडे खाकर भी उन्होंने ना तो अपनी सभ्यता खोई और ना ही वह डरे, अंतोगत्वा अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस परिस्थिति में विचार करने की जरूरत है। भाजपा का वर्तमान सोशल मीडिया जिस तरह से विज्ञापन प्रकाशित कर रहा है। उसकी प्रतिक्रिया होना भी शुरू हो गई है। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे हैं, जिस तरह की स्थिति 1947 और 48 के बीच में देश में देखने को मिली थी। एक बार फिर वही यादें ताजा हो रही हैं। विपक्षी दलों एवं छात्रों ने भी जिस तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया एवं जवाबी तौर पर दी जा रही है, उससे चिंता बढ़ गई है। भारत में कभी भी सत्ता का सिंहासन बंदूक की गोली से नहीं निकलता है यदि ऐसा सिंहासन मिल भी जाता है तो यह ज्यादा दिन टिकता नहीं है। यह भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास है।

लेखक- सनत जैन

बुजुर्गों-दिव्यांगों को चाहिए सुदृढ़ नीति

कभी भारतीय परिवार में बुजुर्ग घर की धुरी हुआ करते थे। संयुक्त परिवार में दादा-दादी, माता-पिता, बच्चे और अन्य सदस्य एक-दूसरे का सहारा बनकर रहते थे। उम्र बढ़ने पर बुजुर्गों को यह चिंता नहीं रहती थी कि बीमारी या असहाय अवस्था में उनकी देखभाल कौन करेगा। परिवार ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा था। लेकिन आज संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवारों में बदल रहे हैं और इसके साथ ही देखभाल एक बड़ी सामाजिक चुनौती बनती जा रही है।

नीति आयोग के अनुसार भारत में बुजुर्गों (60 वर्ष से ऊपर आयु) की आबादी 2022 में लगभग 147 मिलियन थी, जिसके 2050 तक बढकर लगभग 347 मिलियन होने का अनुमान है। इतनी बड़ी बुजुर्ग आबादी की देखभाल केवल पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इसके लिए देश को अभी से एक पेशेवर दीर्घकालीन और व्यवस्थित देखभाल नीति बनाने की आवश्यकता है। आजकल बहुत से परिवारों में केवल एक संतान होती है। उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए बच्चे दूसरे शहरों अथवा विदेशों में चले जाते हैं। निजी क्षेत्र में लंबे कार्य घंटे, बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य की तलाश उन्हें वहीं बसने के लिए विवश कर देती है और माता-पिता अपने पैतृक घर में अकेले रह जाते हैं। बच्चों के लिए बार-बार पैतृक घर आना-जाना संभव नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप बुजुर्ग अपने बच्चों की राह देखते रहते और धीरे-धीरे अकेलेपन, असुरक्षा और निर्भरता का जीवन जीने लगते हैं। कभी-कभी स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि विदेश में रहने वाले बच्चे माता-पिता की बीमारी के समय और कुछ मामलों में अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाते। यह केवल भावनात्मक पीड़ा का विषय नहीं है, बल्कि बदलती सामाजिक संरचना की एक गंभीर वास्तविकता है। पीढ़ियों के बीच बढ़ता विचारों का अंतर भी इस समस्या को जन्म देता है। कई बुजुर्ग अपनी पारंपरिक पारिवारिक प्रभुता छोड़ना नहीं चाहते, जबकि नई पीढ़ी स्वतंत्र जीवन और अपने निर्णयों को प्राथमिकता देती है। इससे मतभेद और टकराव पैदा होते हैं। कभी-कभी बच्चे अलग हो जाते हैं और पीछे रह गए बुजुर्गों की स्थिति अत्यंत कठिन हो जाती है। ऐसे समय में उन्हें केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि साथ, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है। देखभाल की आवश्यकता केवल बुजुर्गों के लिए ही नहीं है बल्कि गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, ऑपरेशन के बाद के मरीज, प्रसूति के बाद जच्चा-बच्चा की देखभाल, एकल स्त्री-पुरुष, मानसिक विकारों से जूझ रहे लोग, बच्चे और दिव्यांग व्यक्ति भी पेशेवर देखभालकत्रा की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक परिस्थितियों में पारंपरिक पारिवारिक देखभाल पर्याप्त नहीं होती। प्रशिक्षित देखभालकत्रा ऐसी परिस्थितियों में परिवार का महत्वपूर्ण सहारा बन सकता है।

एक संगठित होम-केयर व्यवस्था ऐसे परिवारों के लिए बड़ी राहत बन सकती है। भारत में 26.8 मिलियन भारतीय दिव्यांगता के साथ जीवन जी रहे हैं। दिव्यांग व्यक्तियों की समस्या तो और भी गंभीर है। जो दिव्यांग अपने दैनिक कार्यों के लिए पूरी तरह माता-पिता पर निर्भर हैं, माता-पिता के वृद्ध होने या निधन के बाद उनकी देखभाल कौन करेगा? यह दिव्यांग के माता-पिता के लिए गंभीर चिंतन का विषय हमेशा रहता है। बहन एवं अन्य रिश्तेदार होने पर भी विवाह, रोजगार और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उनके लिए निरंतर देखभाल करना कठिन हो जाता है। दिव्यांग व्यक्ति को माता-पिता के बाद कुछ परिस्थितियों में पारिवारिक पेंशन का अधिकार होता है, लेकिन पेंशन अकेली देखभाल की गारंटी नहीं है। उनके लिए दीर्घकालीन आवास, स्वास्थ्य सेवा, प्रशिक्षित व पेशेवर देखभालकर्ता और सामाजिक सुरक्षा की समग्र व्यवस्था जरूरी है। इस चुनौती का समाधान एक मजबूत देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में है जिसमें परिवार, प्रशिक्षित देखभालकत्रा, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं, स्थानीय संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन और सरकार मिलकर काम करें। प्रत्येक जिले में आवश्यकता के अनुसार व्यावसायिक केयर सेंटर तथा प्रशिक्षित होम केयर सेवाओं का नेटवर्क विकसित किया जा सकता है, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति को अपने घर पर ही देखभाल उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही देखभाल को भारत में मान्यता प्राप्त व्यवसाय बनाया जाना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, परीक्षा और प्रमाणपत्र की व्यवस्था हो। प्रशिक्षित व्यक्ति को बुजुर्गों की दैनिक देखभाल, प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छता, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, दिव्यांगों की सहायता तथा गंभीर रोगियों की आवश्यक देखभाल का प्रशिक्षण दिया जाए। इससे देखभाल की गुणवत्ता बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष संभावनाएं हैं। भारतीय घरों में महिलाएं लंबे समय से देखभाल की जिम्मेदारी निभाती आई हैं। यदि उनके अनुभव को औपचारिक प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र से जोड़ा जाए तो देखभाल का काम उनके लिए सम्मानजनक और नियमित रोजगार का माध्यम बन सकता है। भारत में परिवार का स्वरूप, जनसंख्या की आयु संरचना और जीवन की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। इसलिए देखभाल की पुरानी व्यवस्था को नए समय के अनुरूप बदलना होगा। बुजुर्गों, बीमारों और दिव्यांगों की देखभाल को केवल परिवार की निजी जिम्मेदारी मानना अब पर्याप्त नहीं है। समय की मांग है कि भारत देखभाल को एक संगठित सामाजिक व्यवस्था और सम्मानजनक व्यवसाय का स्वरूप दे। इसके लिए भारत को चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, स्वीडन और डेनमार्क देशों के माडल का अध्ययन करना चाहिए। केन्द्र तथा राज्यों को मिलकर देखभाल क्षेत्र को औपचारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जल्द राष्ट्रीय नीति निर्धारण करनी चाहिए। एक मजबूत देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र हमारे बुजुर्गों और निर्भर नागरिकों को सुरक्षा और सम्मान देगा, परिवारों का बोझ कम करेगा, महिलाओं व युवाओं को रोजगार देगा।

सत्यपाल वशिष्ठ, स्वतंत्र लेखक

यूपीआई शुल्क

सुविधाओं का विस्तार या उपभोक्ता पर बोझ ?

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में यूपीआई केवल भुगतान का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि वह रोजमर्रा के आर्थिक व्यवहार का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सब्जी वाले से लेकर बड़े कारोबारी तक, टैक्सी से लेकर ऑनलाइन खरीदारी तक और घरेलू लेन-देन से लेकर व्यावसायिक भुगतान तक-यूपीआई ने पैसे के लेन-देन की आदत, गति और भाषा तीनों बदल दी हैं। ऐसे में यूपीआई से जुड़े शुल्क की व्यवस्था केवल बैंकिंग या फिनटेक कंपनियों का कारोबारी विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध उपभोक्ता की आदत, छोटे व्यापार की लागत और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा से है। यहां एक तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। सितंबर 2026 में सरकार ने जो नया ढांचा स्पष्ट किया है, उसके अनुसार व्यक्ति से व्यक्ति यानी पी2पी को यूपीआई भुगतान किसी भी राशि पर नि:शुल्क रहेगा। रू.2,000 तक के व्यापारी भुगतान पर भी एमडीआर नहीं है। रू.2,000 से अधिक के कुछ पी2एम यानी ग्राहक से व्यापारी भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर का प्रावधान किया गया है और रू.75,000 या उससे अधिक के लेन-देन पर प्रति लेन-देन अधिकतम रू. 300 की सीमा रखी गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह शुल्क ग्राहक से सीधे वसूल किया जाने वाला लेन-देन शुल्क नहीं है, बल्कि व्यापारी-पक्ष का एमडीआर है।

फिर भी इस बदलाव को केवल शुल्क लगा या नहीं लगा के प्रश्न तक सीमित करना उचित नहीं होगा। असली सवाल यह है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लंबे समय तक टिकाऊ कैसे बनाया जाए और उसकी लागत किसके हिस्से में जाए। यूपीआई की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी सरलता और लगभग बिना लागत की अनुभूति रही है। अगस्त 2026 में यूपीआई पर करीब 24.51 अरब लेन-देन हुए, जिनका कुल मूल्य लगभग रू.29.82 लाख करोड़ रहा। यह आंकड़ा बताता है कि यूपीआई अब किसी वैकल्पिक भुगतान माध्यम की श्रेणी में नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक जीवन के बुनियादी ढांचे में शामिल हो चुका है। यूपीआई के इस विस्तार के पीछे एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी हुआ है। लोगों ने डिजिटल भुगतान को केवल सुविधा नहीं, स्वाभाविक व्यवहार मान लिया है। पहले दस रुपये, पचास रुपये या सौ रुपये के लिए जेब से नकद निकालना सामान्य थाय आज वही भुगतान मोबाइल से कुछ सेकंड में हो जाता है। जब कोई सेवा वर्षों तक नि:शुल्क उपलब्ध रहती है तो उपभोक्ता उसके पीछे मौजूद तकनीकी, बैंकिंग और साइबर-सुरक्षा लागत को लगभग भूल जाता है। इसलिए बाद में किसी प्रकार का शुल्क या लागत सामने आने पर स्वाभाविक रूप से असहजता पैदा होती है।

यहीं आधुनिक बाजार व्यवस्था की एक बड़ी विसंगति दिखाई देती है। अनेक डिजिटल और उपभोक्ता सेवाएं पहले मुफ्त, अत्यंत सस्ती या भारी छूट के साथ उपलब्ध कराई जाती हैं। उपभोक्ता को उस सुविधा का अभ्यस्त बनाया जाता है, बाजार में उसका व्यवहार बदलता है और प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने के बाद लागत की नई संरचना सामने आती है। ओला-उबर जैसी सेवाओं से लेकर ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल सदस्यता और विभिन्न प्लेटफॉर्म सेवाओं तक इस मॉडल के अलग-अलग रूप दिखाई देते हैं। यह कहना उचित नहीं होगा कि हर मामले में यही रणनीति अपनाई जाती है, लेकिन उपभोक्ता के दृष्टिकोण से प्रश्न महत्वपूर्ण है-यदि किसी सेवा की दीर्घकालिक लागत है तो उसकी जानकारी शुरूआत से स्पष्ट क्यों न हो? यूपीआई के मामले में यह प्रश्न और गंभीर है क्योंकि इसके उपयोगकर्ता केवल शहरी मध्यमवर्ग नहीं हैं। छोटे दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू उद्यमी, ग्रामीण उपभोक्ता और पहली बार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े लोग भी इसके बड़े हिस्से हैं। सरकार की 2025 की प्रोत्साहन योजना में भी छोटे व्यापारियों के रू.2,000 तक के भीम-यूपीआई भुगतान को शून्य एमडीआर के दायरे में रखते हुए रू.1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ाना और भुगतान ढांचे को मजबूत करना था।

इसलिए शुल्क की किसी भी व्यवस्था का पहला सिद्धांत होना चाहिए-छोटे भुगतान और छोटे कारोबार की रक्षा। रू.100, रू.500 या रू.1,000 के भुगतान पर लागत बढ़ाने वाला मॉडल डिजिटल समावेशन की भावना के विपरीत जा सकता है। इसके विपरीत बड़े व्यावसायिक भुगतान से जुड़ी लागत को अलग तरीके से देखा जा सकता है, बशर्ते शुल्क पारदर्शी, सीमित और पूर्व घोषित हो तथा उसका भार अनुचित रूप से ग्राहक पर न डाला जाए। यहां डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। यूपीआई के व्यापक प्रसार ने कार्ड भुगतान को रोजमर्रा के छोटे भुगतानों में पीछे धकेला है। यदि यूपीआई के कुछ बड़े व्यापारी लेन-देन पर लागत बढ़ती है तो कुछ कारोबारी वैकल्पिक भुगतान माध्यमों की ओर देख सकते हैं। कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या अन्य डिजिटल माध्यम फिर कुछ क्षेत्रों में अधिक सक्रिय हो सकते हैं। इससे भुगतान बाजार में विविधता बढ़ सकती है, लेकिन यदि उपभोक्ता को हर माध्यम में अलग-अलग शुल्क, सुविधा और शर्तों का सामना करना पड़े तो डिजिटल भुगतान की सरलता कमजोर भी हो सकती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य केवल माध्यम बदलना नहीं, बल्कि उपभोक्ता को बेहतर विकल्प देना होना चाहिए।

दूसरी ओर यूपीआई को मुफ्त बनाए रखने की भी कीमत है। भुगतान प्रणाली को चौबीसों घंटे चलाने के लिए बैंकिंग सर्वर, डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने वाली प्रणालियां, ग्राहक सहायता और तकनीकी उन्नयन पर लगातार खर्च होता है। जैसे-जैसे लेन-देन बढ़ते हैं, वैसे-वैसे विश्वसनीयता और क्षमता पर निवेश की आवश्यकता भी बढ़ती है। सरकार की 2025 की योजना में भी तकनीकी विफलताओं को घटाने और सिस्टम अपटाइम सुधारने को प्रोत्साहन से जोड़ा गया था। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि यूपीआई की हर सेवा हमेशा मुफ्त रहे या नहीं, सवाल यह होना चाहिए कि उसकी लागत का न्यायपूर्ण और पारदर्शी वितरण कैसे हो। सरकार, बैंक, फिनटेक कंपनियां और भुगतान नेटवर्क यदि इस व्यवस्था से आर्थिक लाभ लेते हैं तो उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा, विश्वसनीयता और नवाचार पर पर्याप्त निवेश हो। शुल्क का उद्देश्य केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि बेहतर डिजिटल भुगतान व्यवस्था के निर्माण से जुड़ा होना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात उपभोक्ता विश्वास की है। डिजिटल अर्थव्यवस्था विश्वास पर चलती है। यदि आज किसी सेवा को ह्यमुफ्तह्व बताया जाए और कल अचानक उसकी लागत सामने आए, तो उपभोक्ता में अविश्वास पैदा हो सकता है। इसलिए भविष्य में किसी भी डिजिटल भुगतान व्यवस्था की शुरूआत करते समय उसकी संभावित लागत, शुल्क संरचना और उसे लागू करने की परिस्थितियां पहले से स्पष्ट होनी चाहिए। उपभोक्ता को यह पता होना चाहिए कि कौन-सी सेवा नि:शुल्क है, किस पर लागत है, लागत कौन वहन करेगा और उसका अधिकतम स्तर क्या होगा। भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार कर रहा है। ऐसे समय में यूपीआई की सफलता को केवल लेन-देन की संख्या से नहीं, बल्कि उसकी स्थिरता, सुरक्षा, पहुंच और उपभोक्ता विश्वास से मापना होगा। भारत की विकास-आकांक्षाओं के लिए उत्पादकता, नवाचार और मजबूत डिजिटल आधारभूत ढांचा महत्वपूर्ण हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी भारत की उत्पादकता और नवाचार क्षमता को दीर्घकालिक विकास से जोड़ता है।

यूपीआई शुल्क की बहस इसलिए वास्तव में ह्यशुल्क बनाम मुफ्तह्व की बहस नहीं है। यह उस आर्थिक दर्शन की परीक्षा है जिसमें डिजिटल सुविधा आम आदमी तक सस्ती, सरल और सुरक्षित रूप में पहुंचती है। छोटे भुगतान मुफ्त रहें, छोटे व्यापारियों पर अनावश्यक भार न पड़े, बड़े व्यावसायिक लेन-देन में लागत की तार्किक व्यवस्था हो, शुल्क की जानकारी पहले से सार्वजनिक हो और उससे प्राप्त संसाधन भुगतान प्रणाली की सुरक्षा व क्षमता बढ़ाने में लगें, ऐसा संतुलन ही टिकाऊ रास्ता हो सकता है। भारत को डिजिटल भुगतान का विस्तार रोकना नहीं, बल्कि उसकी अगली पीढ़ी तैयार करनी है। यूपीआई की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने भुगतान को बैंक की शाखा और बटुए की सीमा से निकालकर मोबाइल की स्क्रीन तक पहुंचा दिया। अब अगली चुनौती यह है कि यह सुविधा आर्थिक रूप से टिकाऊ भी रहे और आम उपभोक्ता के लिए सहज भी। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखने वाले भारत में डिजिटल भुगतान केवल तकनीक नहीं, आर्थिक जीवन की धड़कन है। इसलिए इसकी कीमत तय करते समय बाजार की कमाई से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए-ह्यउपभोक्ता का विश्वास, छोटे कारोबार की क्षमता और डिजिटल भारत की दीर्घकालिक विश्वसनीयता।

(लेखक - ललित गर्ग)
(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

द्वारका में बनेगा 152 करोड़ का 'दिल्ली सदन', सीएम रेखा गुप्ता ने दी मंजूरी

नई दिल्ली, 19 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली सरकार द्वारका में करीब 152 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली सदन का निर्माण कराएगी। यह राज्य अतिथि गृह देश-विदेश से दिल्ली आने वाले गणमान्य लोगों, सरकारी अधिकारियों और अन्य सरकारी अतिथियों के ठहरने के लिए बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार के पास अभी अपना कोई समर्पित राज्य अतिथि गृह नहीं है। ऐसे में बाहर से आने वाले अतिथियों के ठहरने और उनकी मेजबानी में कई बार परेशानी होती है। प्रस्तावित दिल्ली सदन का निर्माण द्वारका के सेक्टर-19 में भूखंड संख्या-5 पर किया जाएगा। इसके लिए करीब 3,899.42 वर्गमीटर जमीन उपलब्ध है।

अधिकारियों के मुताबिक, यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त ऐसा भवन तैयार किया जाएगा, जिसमें सरकारी अतिथियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक ठहरने की व्यवस्था होगी।

दिल्ली में पकड़ी गई पाकिस्तानी हेरोइन

नई दिल्ली, 19 सितंबर (वेब वार्ता)। गैंगस्टर रोहित गोदारा के मुख्य सहयोगी महेंद्र डेलाना द्वारा चलाए जा रहे एक बड़े नार्को-एक्सटॉर्शन मॉड्यूल का दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और वडोदरा सिटी क्राइम ब्रांच ने संयुक्त ऑपरेशन में भंडाफोड़ किया है।

पुलिस ने टीम ने पाकिस्तान में बनी दो किलाग्राम हेरोइन बरामद करते हुए राजस्थान के चुरू के कुलदीप स्वामी को गिरफ्तार किया है। आरोपित वडोदरा सिटी क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज 10 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में वांछित था। जिसमें रंगदारी की रकम की पहली किस्त दिल्ली में ली जानी थी। यह सिंडिकेट कई स्तरों वाला नेटवर्क चलाता था, जो रंगदारी के पैसे इकट्ठा करने और ड्रग्स की तस्करी के लिए काम करता था।

नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल हुईं रेखा गुप्ता

फतेहगढ़ साहिब, 19 सितंबर (वेब वार्ता)। पंजाब को नशा-मुक्त बनाने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा शुरू की गई नशा मुक्त पंजाब यात्रा के दूसरे दिन शनिवार को श्री फतेहगढ़ साहिब की पवित्र धरती से हुई। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। उन्होंने गुरुद्वारा में मत्था टेका और कहा कि पंजाब के युवाओं को नशे से बचाने के लिए पूरा देश इस अभियान के साथ है।

मीडिया से बातचीत के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह भूमि छोटे साहिबजादों की शहादत की स्मृति से जुड़ी है और यहां से पंजाब के लोगों को नशे के खिलाफ लड़ाई के लिए शक्ति मिलने की प्रार्थना की गई है। पंजाब जिस तरह नशे की गिरफ्त में है, उसके खिलाफ हम सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। हमें पंजाब और युवाओं को सुरक्षित करना है। इस लड़ाई में पूरा देश पंजाब के साथ है। दिल्ली पंजाब के साथ है और मैं भी पंजाब के साथ हूं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि नशे के खिलाफ यह संकल्प गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचना चाहिए तथा अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए।

जामिया में ऑड सेमेस्टर परीक्षा के लिए 25 सितंबर से भर सकेंगे फॉर्म

नई दिल्ली, 19 सितंबर (वेब वार्ता)। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने ऑड सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। नियमित और पार्ट टाइम पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म 25 सितंबर से 20 अक्तूबर तक ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। इसमें सभी अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के साथ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा के छात्र फॉर्म भर सकेंगे। बैकलॉग पेपर वाले छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं पीएचडी कोर्स वर्क के छात्रों के लिए भी ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म इसी अवधि में भरे जाएंगे। इसमें सत्र 2025-26 के सेमेस्टर-2 और सत्र 2026-27 के सेमेस्टर-1 के शोधार्थी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संजू सैमसन से की मुलाकात

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को बनाया जन कौशल केंद्र का ब्रांड एंबेसडर

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन से खास मुलाकात की। सैमसन को मोती नगर के जन कौशल केंद्र का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।

सीएम रेखा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, संजू का दिल्ली से एक खास रिश्ता है, जहां उन्होंने अपने शुरूआती साल बिताए और अपने क्रिकेट करियर की शुरूआत की। अब, मदन लाल खुराना फाउंडेशन द्वारा नियुक्त जन कौशल केंद्र, मोती नगर के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर वह दिल्ली के युवाओं को कौशल, अवसरों और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करेंगे। इस मौके पर विधायक श्री हरीश खुराना, ट्रिनिटी फाउंडेशन और आईएसीटी एजुकेशन के वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद थे।

संजू सैमसन का प्रदर्शन अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई टी20 इंटरनेशनल सीरीज में शानदार रहा। पहले मैच में फ्लॉप रहने के बाद सैमसन ने दूसरे और तीसरे टी20 में अर्धशतकीय पारी खेली। दूसरे टी20 में संजू ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में 57 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान सैमसन ने 7 चौके और 4 छक्के लगाए।

वहीं, तीसरे टी20 में भी सैमसन का बल्ला

जमकर गरजा। उन्होंने 35 गेंदों का सामना करते हुए 50 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। संजू ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 9.5 ओवर में 142 रन जोड़े। अभिषेक इस दौरान फुल मेंबर देशों की तरफ से सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने महज 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 221 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन बनाकर ऑलआउट हुई। भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया।

संजू सैमसन के लिए यह साल अब तक शानदार गुजरा है। टी20 विश्व कप 2026 में उनका प्रदर्शन दमदार रहा था और उन्होंने भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने टूर्नामेंट में खेले 5 मैचों में 321 रन बनाए थे और वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे।

दिल्ली पुलिस ने 2 लाख रुपये की धोखाधड़ी और चोरी का मामला सुलझाया, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 19 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी और चोरी के एक मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग (सीसीएल) को पकड़ा है, साथ ही चोरी हुए सोने के झुमके भी बरामद किए हैं।

द्वारका जिला पुलिस के अनुसार, आरोपी ने एक महिला को 2 लाख रुपये बांटने का लालच देकर उसके सोने के गहने धोखे से ले लिए। पीड़िता को धोखा देने के लिए नकली नोटों का इस्तेमाल किया गया था।

सोने के गहने चोरी होने की शिकायत के बाद 10 सितंबर को डाबरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता राजबाला (सतेंद्र कुमार की पत्नी) से मिली। शुरूआती पूछताछ के दौरान, उन्होंने पुलिस को बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनसे सोने की बालियों की एक जोड़ी और सोने का एक पेंडेंट ले लिया था। जांच के दौरान, पुलिस टीम द्वारा अपराध वाली जगह और उसके आस-पास लगे कैमरों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। फुटेज में दो लड़के महिला के पास पैदल आते और उससे एटीएम की जगह के बारे में पूछते हुए दिखे।

केंद्र सरकार ने 14 नए जजों की नियुक्ति को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 19 सितंबर (वेब वार्ता)। केंद्र सरकार ने शनिवार को अलग-अलग हाई कोर्ट में 14 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जजों की सूची जारी करते हुए लिखा, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, राष्ट्रपति न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट में कुल 7 जजों की नियुक्ति की गई है। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को स्थाई जज नियुक्त किया गया है। वहीं, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है। अरुण भारद्वाज अभी दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं। इससे पहले, 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजों के लिए 8 न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश भेजी थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने उनमें से सिर्फ 7 नामों को मंजूरी दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 60 है।

दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 7 नामों पर लगी मुहर

फिलहाल वहां 44 जज काम कर रहे हैं, यानी 16 पद खाली हैं।

झारखंड हाई कोर्ट में तीन नए जज नियुक्त किए गए हैं, जिनमें मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा शामिल हैं। झारखंड हाई कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 25 है। अभी तक यहां 13 जज काम कर रहे थे और 12 पद खाली थे। नई नियुक्तियों के बाद, हाई कोर्ट में काम करने वाले जजों की संख्या बढ़कर 16 हो जाएगी। सरकार ने शनिवार को यश पॉल बोर्नी की जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर को हुई बैठक में हाई कोर्ट जज के तौर पर उनकी नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट में तीन न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त जज के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दी। जिन तीन न्यायिक अधिकारियों को प्रमोट किया गया है, उनमें उषा रानी, केएस भरत कुमार और नेराले वीरभद्रैया भवानी शामिल हैं।

दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट की कई उड़ानें हुईं प्रभावित

नई दिल्ली, 19 सितंबर (वेब वार्ता)। परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण शनिवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट की कई उड़ानें विलंबित या रद्द कर दी गईं, जिससे सैकड़ों यात्री प्रभावित हुए। अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें या एयरपोर्ट पर मौजूद टीमों से मदद लें। दिल्ली एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक एडवाइजरी में कहा, स्पाइसजेट की कुछ उड़ानों के संचालन में व्यवधान के कारण यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। दिल्ली एयरपोर्ट की टीमें प्रभावित यात्रियों की सहायता करने और जरूरी सहयोग के लिए एयरलाइन और संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इससे पहले, 15 सितंबर को भी ऐसी एक घटना हुई। उस समय दुबई जाने वाले विमानों के बार-बार रीशेड्यूल और देर होने के बाद स्पाइसजेट के लगभग 200 यात्रियों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन किया था।

डीयू छात्रसंघ चुनाव में फर्जी वोटिंग पर राहुल गांधी से माफी की मांग

नई दिल्ली, 19 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (डूसू) चुनाव के लिए वोटों की गिनती शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है, नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। डूसू चुनाव को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है।

भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक सिद्धार्थ यादव ने एनएसयूआई से जुड़ी एक छात्रा के फर्जी आईडी से वोट डालते हुए पकड़े जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, रोज वोट चोरी का ढोल पीटने वाले राहुल गांधी की पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई की एक कार्यकर्ता छात्र संघ चुनावों में फर्जी आईडी कार्ड के साथ मतदान करती पकड़ी गई।

सिद्धार्थ यादव ने कहा, जब छात्रा पकड़ी गई तो उसने खुद कबूला कि अनेक एनएसयूआई के कार्यकर्ता फर्जी आईडी कार्ड्स के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में मतदान करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से हर जगह वोट चोरी देखने का कारण यही है कि खुद की पार्टी और खुद के छात्र संगठन में इतने बड़े पैमाने पर वोट चोरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की नर्सरी ऐसी होगी, उसकी यूनिवर्सिटी कैसी होगी इसकी कल्पना करना भी कठिन है।

उनकी पार्टी कितनी गंभीर है

भाजपा नेता सिद्धार्थ यादव ने कहा, ह्लराहुल गांधी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उनको शर्म आनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। छात्र संघ चुनाव में, जहां केवल युवा मतदान कर रहा है, वहां पर चुनाव प्रभावित करना और अशुचिता फैलाना राहुल गांधी और उनकी पार्टी की पहचान बन चुका है। यह दशार्ता है कि लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी कितनी गंभीर है।

भरोसा है कि मैं जीतूंगा

एनएसयूआई के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार वीर छत्रथ ने कहा, हम बहुत सकारात्मक हैं। हमें छात्रों से जबरदस्त समर्थन मिला है। एएसएपी से सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार पंकज कुमार ने कहा, हर बार की तरह इस बार भी बहुत उत्साह है। गिनती शुरू हो गई है और नतीजे जल्द ही पता चल जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में की गई कड़ी मेहनत के आधार पर मुझे बहुत अच्छे नतीजों की उम्मीद है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जीतूंगा।

दिल्ली में नाबालिग लड़की से गैंगरेप और हत्या मामले का एनसीडब्ल्यू ने लिया संज्ञान, कमिश्नर को लिखा पत्र

नई दिल्ली, 19 सितंबर (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने आउटर नॉर्थ दिल्ली में 16 साल की लड़की से गैंगरेप और हत्या का मामला खुद संज्ञान में लिया है। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर समयबद्ध और विस्तृत जांच, सख्त कानूनी कार्रवाई और सभी फोरेंसिक सबूतों को सुरक्षित रखने की मांग की है।

दरअसल नाबालिग लड़की की गैंगरेप के बाद चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। लड़की का शव एक खुले मैदान में मिला था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पोक्सो एक्ट और बीएनएस के तहत उचित कार्रवाई करने और जहां कानूनी रूप से लागू हो, वहां 16-18 साल के आरोपियों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 15 के तहत शुरूआती जांच करने को भी कहा है। आयोग ने पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा, कानूनी मदद, काउंसलिंग और मुआवजे के साथ-साथ सात दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है।

13 सितंबर को उत्तरी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में कुशक रोड पर जयपाल राणा के खेत के पास सड़ी-गली लाश मिली थी। शव की हालत ऐसी थी कि पुलिस शुरू में यह भी तय नहीं कर पाई कि शव लड़के का है या लड़की का। पुलिस को जांच में पता चला कि गैंगरेप के बाद हत्या कर शव फेंका गया था। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को 4 लोगों ने अंजाम दिया, जिसमें 3 नाबालिग थे।

दर्ज नहीं कराई थी रिपोर्ट

जांच में पता चला कि पीड़िता आरोपियों को जानती थी और उनके साथ टेंपो में सफर कर रही थी। पुलिस के अनुसार सफर के दौरान सभी ने शराब पी और फिर लड़की से दुष्कर्म किया। इसके बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई और शव को खुले खेत में फेंक दिया गया। लावारिस कुत्तों ने शव के कुछ हिस्से खा लिए थे और पीड़िता का एक हाथ शरीर से अलग पड़ा मिला था। पुलिस ने बताया कि लड़की के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी।

फ्लैट में मिले दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल और पत्नी के शव, हत्या के बाद खुदकुशी का शक

नई दिल्ली, 19 सितंबर (वेब वार्ता)। नरेला के महादेव अपार्टमेंट में शनिवार को दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और उनकी पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। दोनों के शव फ्लैट के अंदर मिलने के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शनिवार दोपहर दंपती के बच्चे स्कूल से घर लौटे थे। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

दिल्ली मास्टर प्लान 2047: डीडीए ने आर्किटेक्ट्स और एसपीए विशेषज्ञों के साथ चर्चा की

नई दिल्ली, 19 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 (एमपीडी 2047) के प्रभावी और सहभागी कार्यान्वयन को सुगम बनाने और हितधारकों के बीच व्यापक समझ विकसित करने के उद्देश्य से, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने आर्किटेक्ट्स, योजनाकारों और अन्य पेशेवर हितधारकों के साथ परामर्श किया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उपराज्यपाल टीएस संधू के निर्देश पर डीडीए द्वारा आयोजित हितधारक परामर्श के छठे और सातवें दौर में भाग लेने वाले हितधारकों को दिल्ली के नियोजित विकास के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार, सुझाव और प्रतिक्रिया साझा करने का अवसर मिला। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पार्किंग अवसंरचना, यातायात प्रबंधन और पुनर्विकास परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर सुझाव प्राप्त हुए।

ये परामर्श डीडीए के व्यापक तीन महीने के हितधारक संपर्क कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य विभिन्न हितधारक समूहों को शामिल करना, एमपीडी 2047 के प्रावधानों की बेहतर समझ को बढ़ावा देना और इसके प्रभावी और सहभागी कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के दृष्टिकोण को शामिल करना है। बयान में कहा गया कि दिल्ली की योजना एवं विकास से जुड़े विभिन्न विषयगत क्षेत्रों और हितधारक समूहों को शामिल करते हुए चल रही प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग 20 परामर्श बैठकें आयोजित करने की योजना है। छठी परामर्श बैठक में वास्तुकार, योजनाकार और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी), वास्तुकला परिषद, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (एसपीए), नगर योजनाकार संस्थान (आईटीपीआई), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सातवीं परामर्श बैठक में वास्तुकार और योजनाकार शामिल हुए

परामर्श बैठकों के दौरान, डीडीए ने एमपीडी 2047 का संक्षिप्त विवरण और एक सतत, हरित और रहने योग्य राष्ट्रीय राजधानी के निर्माण के अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। हितधारकों को मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न स्थानिक विकास नीतियों से अवगत कराया गया, जिनमें पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी), भूमि पूलिंग क्षेत्र, उच्च घनत्व गलियारे (एचडीसी) और निम्न घनत्व क्षेत्र (एलडीए) शामिल हैं।

उपराज्यपाल ने थाना दिवस जनसुनवाई में लोगों की शिकायतें सुनीं

नई दिल्ली, 19 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शनिवार को पीएस मौर्य एन्क्लेव में थाना दिवस जनसुनवाई में शामिल होकर नागरिकों से संवाद करते हुए उनकी शिकायतें सुनने और तय समय में उनका समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को उनके मुख्य काम के बारे में फिर से याद दिलाया। उन्होंने कहा कि ऐसी पुलिसिंग जो दिखे, आसानी से उपलब्ध हो और तुरंत प्रतिक्रिया दे, साथ ही भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस (बिल्कुल बर्दाश्त न करना) की नीति अपनाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एफआईआ की कॉपी तुरंत मिले, केस के बारे में नियमित अपडेट दिए जाएं, बीट और नाइट पेट्रोलिंग मजबूत हो और महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाए। उपराज्यपाल ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की और इस बात पर जोर दिया कि भरोसा कायम करने और दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन के साथ सक्रिय साझेदारी बहुत जरूरी है।

बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा

29 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली, 19 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शनिवार को घोषणा की कि मयूर विहार बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 29 सितंबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे।

प्रवेश साहिब सिंह ने कहा, बहुत खुशी का अवसर है कि यह प्रोजेक्ट काफी देरी से चल रहा था। क्योंकि पिछली सरकार ने क्लियरेंस नहीं ली थी। जिससे इसमें काफी समस्या थी। सरकार बनते ही जब मैंने आकर देखा तो हमें बताया गया कि पिछली सरकार का कोई भी प्रतिनिधि यहां नहीं आया था। हमने मुख्यमंत्री से बात करके इसको प्राथमिकता पर लिया। मैंने पिछले वर्ष ही कहा था कि 2026 के मध्य में इसको पूरा कर दिया जाएगा। अब हम लोगों ने इसको पूरा करके दिखाया है।

प्रवेश साहिब सिंह ने कहा, 29 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे और अगले दिन से दिल्ली के लाखों लोगों के लिए समर्पित हो जाएगा। यह देश का पहला ऐसा फ्लाईओवर है कि जहां पर साइकिल ट्रैक और पैदल चलने की व्यवस्था की गई है। यह फ्लाईओवर यमुना नहीं के ऊपर बना है। यह एक तरह से यमुना रिवरफ्रंट का भी काम करेगा। पूरी यमुना मईया दिखाई दे रही हैं और हराभरा दिखाई दे रहा है। हजारों लोग अभी से यहां आकर सैर करना शुरू कर दिए हैं।

प्रवेश साहिब सिंह ने आगे कहा, लोगों को काफी आनंद आने वाला है। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार तो कोई काम ही नहीं करती थी। जिसकी वजह से इसकी लागत भी बढ़ गई और कंपनी को ज्यादा पैसा भी देना पड़ा। जो प्रोजेक्ट तीन वर्ष में बनना था, उसको बनने में 10 वर्ष लग गए। यह पिछली सरकार की नाकामियां रहीं।

इससे पहले प्रवेश साहिब सिंह ने 26 मई को बारापुला फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था। तब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी तो 20 फरवरी को शपथ लेने के बाद हम तुरंत इस रुके हुए प्रोजेक्ट को देखने गए थे। प्रवेश साहिब सिंह ने कहा था कि इसके बाद से हर हफ्ते मेरे कार्यालय से इसे फॉलो किया गया। मैंने पहले भी कहा था कि 30 जून तक इस काम को खत्म कर देंगे। हमारा काम बिल्कुल समय से चल रहा है और यह 30 जून को समय से पूरा हो जाएगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पंजाब के गुरुद्वारा श्री ज्योति सरूप साहिब में शीश नवाया

नई दिल्ली, 19 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को पंजाब स्थित श्री फतेहगढ़ साहिब के गुरुद्वारा श्री ज्योति सरूप साहिब में शीश नवाया। उन्होंने कहा कि वीर साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत की स्मृतियों से जुड़ी यह पावन धरती त्याग, तपस्या, साहस और धर्मनिष्ठा की अमर प्रेरणा है।

मुख्यमंत्री ने गुरु चरणों में पंजाब की सुख-समृद्धि, खुशहाली और प्रत्येक परिवार के कल्याण की अरदास की। उन्होंने कहा कि वाहेगुरु की कृपा सभी पर बनी रहे और सेवा, सत्य एवं सद्भाव का प्रकाश हमारे जीवन को सदैव दिशा देता रहे।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि आज उन्होंने गुरु साहिब से प्रार्थना की कि वे पंजाब के लोगों को राज्य में जारी अत्याचारों और नशीली दवाओं की समस्या की जकड़ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की शक्ति प्रदान करें। हमें पंजाब और उसके युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इस संघर्ष में पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आज ह्यनशामुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने पंजाब पहुंची हैं।

गोदाम में बोरियों से खाद्य सामग्री निकालने का आरोप, वीडियो से मचा हड़कंप

भाकियू टिकैत ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, स्टॉक और अभिलेखों की जांच की मांग

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। तालबेहट तहसील क्षेत्र के थाना बार अंतर्गत बिधा महावत के पास स्थित मुख्य गोदाम में खाद्य सामग्री एवं अनाज की बोरियों से कथित रूप से सामग्री निकाले जाने का मामला सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के मंडल उपाध्यक्ष झांसी कीरत बाबा, निवासी बार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच और गोदाम के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि गोदाम में रखी बोरियों से खाद्य सामग्री अथवा अनाज निकाले जाने की गतिविधियां वीडियो में दिखाई दे रही हैं। शिकायतकर्ता ने वीडियो को साक्ष्य बताते हुए गोदाम में मौजूद वास्तविक स्टॉक का स्टॉक रजिस्टर और आवक-निर्गत अभिलेखों से मिलान कराने की मांग की है। भाकियू नेता ने गोदाम में रखी बोरियों की संख्या, उपलब्ध खाद्य सामग्री और संबंधित अभिलेखों की मौके पर जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि दस्तावेजों में दर्ज स्टॉक और मौके पर उपलब्ध सामग्री में अंतर मिलने पर इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

वीडियो की तकनीकी जांच की मांग

ज्ञापन में वायरल वीडियो की भी तकनीकी जांच कराने का अनुरोध किया गया है। इसके जरिए वीडियो की प्रामाणिकता और उसमें दिखाई दे रही गतिविधियों की वास्तविकता स्पष्ट करने की मांग की गई है।

पुष्टि होने पर एफआईआर की मांग

कीरत बाबा ने कहा कि जांच में यदि खाद्य सामग्री के स्टॉक में कमी, हेराफेरी या किसी अन्य अनियमितता की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रशासन से मामले का शीघ्र संज्ञान लेकर गोदाम का निरीक्षण और स्टॉक सत्यापन कराने की मांग की है। हालांकि, ज्ञापन में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले की वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच और स्टॉक के भौतिक सत्यापन के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

परिवार न्यायालय का बड़ा फैसला

1 लाख प्रतिमाह अंतरिम मेंटेनेंस का आदेश

मुरादाबाद, वेब वार्ता

मुरादाबाद की फैमिली कोर्ट ने इठरर की धारा 144 के तहत चल रहे भरण-पोषण के एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए शहर के एक प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन को 1लाख 20 हजार रुपए प्रतिमाह अंतरिम मेंटेनेंस देने का आदेश दिया है।

मामले में पत्नी की ओर से एडवोकेट नाज़िर पाशा ने पुख्ता दलिलो और सबूतों के साथ पैरवी की। इस मामले में पति शहर के चर्चित न्यूरोसर्जन हैं, जबकि पत्नी भी डॉक्टर है। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष बच्चों की आवश्यकताओं, परिवार की आर्थिक स्थिति, जीवन-स्तर और अन्य संबंधित तथ्यों को रखा गया। इन पहलुओं पर विचार करने के बाद परिवार न्यायालय ने 1लाख 20 हजार रुपए प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण (ट्रंल्लशील्लंल्ली) निर्धारित किया। आदेश के अनुसार यह राशि मामला दाखिल किए जाने की तारीख से देय होगी। इस आधार पर अब तक लगभग 7लाख 20 हजार रुपये की अंतरिम मेंटेनेंस राशि बनने की बात सामने आई है। मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट नाज़िर पाशा ने आदेश पर खुशी जताते हुए कहा, कोर्ट ने बच्चों का हक दिया है। हमें इंसाफ मिला है।

संक्षिप्त वार्ता

साण्डी में पति-पत्नी का विवाद हिंसक

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। साण्डी कस्बे के मुंशीगंज मोहल्ले में पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद उस समय हिंसक हो गया, जब दोनों के बीच गाली-गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई। पुलिस के अनुसार विवाद के दौरान पत्नी ने पति दीपक के गुप्तांग पर चोट पहुंचाई, जबकि इसके जवाब में दीपक ने पत्नी के साथ मारपीट करते हुए उसकी नाक को दांत से काट लिया। महिला का उपचार जिला अस्पताल हरदोई में कराया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मुंशीगंज निवासी दीपक पुत्र चुन्नीलाल की शादी करीब दस वर्ष पूर्व हुई थी। पारिवारिक विवाद के चलते उसकी पत्नी करीब छह माह पूर्व मायके चली गई थी। पुलिस की प्राप्त सूचना के मुताबिक, इसके बाद महिला कुछ समय अपने चचेरे देवर के साथ रही।

डीएम की अध्यक्षता में तहसील सदर में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस

वेब वार्ता, बहराइच। आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान

दिवसों की कड़ी में माह सितम्बर के शनिवार को तहसील सदर में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। इस अवसर पर डीएम ने पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार धनवंता, उप जिलाधिकारी अमन देयोल, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार, डीडीओ राज कुमार, पीडी डीआरडीए मनीष कुमार व अन्य अधिकारियों के साथ फरियादियों की समस्याओं की गम्भीरतापूर्वक सुनवाई की और निस्तारण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। डीएम ने क्षेत्र के व्यक्तियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होनें स्पष्ट किया कि जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सर्पदंश जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में हुआ गोष्ठी का आयोजन

वेब वार्ता, बहराइच

सर्पदंश से होने वाली मृत्यु पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा

अधिकारी डॉ. संजय कुमार की अध्यक्षता में सीएमओ सभागार में एक गोष्ठी का आयोजित किया गया।

एसीएमओ श्रीमती डॉ. संतोष राना ने बताया कि नए वर्ष के साथ राज्य सरकार द्वारा सीएचसी स्तर तक सर्पदंश चिकित्सा की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। अब यह संपूर्ण उपचार सीएचसी स्तर तक पूरी तरह नि:शुल्क प्रदान किया जा रहा है। आपने मेडिकल कॉलेज समेत सभी ब्लॉक से सर्पदंश की रिपोर्टिंग में और सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया जिससे कि बचाव एवं चिकित्सा दोनों को बल मिलने की बात कही। प्रशिक्षक एवं जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ. निर्मेष श्रीवास्तव ने बताया कि सभी सर्प विषैले नहीं होते और सर्पदंश के पश्चात बिना समय गंवाए पीड़ित को सरकारी चिकित्सालय में भर्ती कराना चाहिए जहां चिकित्सक 24 घंटों तक उसे निगरानी में रखेंगे। विष के लक्षण आने पर पीड़ित को आवश्यकता अनुसार एंटी स्नेक वेनम के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। यदि सांप जहरीला नहीं है तो एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं होती परन्तु अन्य चिकित्सा अंग एवं प्राण रक्षा हेतु आवश्यक है। सही चिकित्सा होने पर मृत्यु का खतरा लगभग शतप्रतिशत समाप्त हो जाता है। इसके लिए सांप के काटने के बाद उसी दिन उपचार प्रारंभ करना अत्यंत आवश्यक है।

गणपति विसर्जन को लेकर राप्ती घाट का निरीक्षण,व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश

वेब वार्ता, कमर खान

बलरामपुर। श्री गणपति महोत्सव के विसर्जन को लेकर आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर की ओर से तैयारियों को तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में अध्यक्ष

प्रतिनिधि डीपी सिंह बैस ने श्री गणपति के ंद्रीय समन्वय समिति के पदाधिकारियों एवं अन्य गणमान्य जनों के साथ राप्ती घाट का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन को ध्यान में रखते हुए घाट की साफ-सफाई, स्वच्छता व्यवस्था एवं समतलीकरण का जायजा लिया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए विसर्जन स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया तथा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर चर्चा की गई। अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह बैस ने कहा कि नगर पालिका परिषद बलरामपुर नगर के श्रद्धालुओं की सुविधा एवं धार्मिक आयोजनों को व्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सदैव तत्पर है। गणपति विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो,इसके लिए संबंधित व्यवस्थाओं को समय से पूरा कराया जाएगा।

मिशन सेफ फ्यूचर 3.0 के तहत 65 स्कूली वाहन सीज, 14 स्कूलों को नोटिस

वेब वार्ता, कानपुर

मिशन सेफ फ्यूचर 3 .0 के तहत कानपुर संभागीय परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों ने 65 स्कूली वहनो पर सीज की कार्यवाही की और 14 स्कूल प्रबंधको को नोटिस जारी किया।

कानपुर मण्डल आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि मा. उच्च

न्यायालय द्वारा जारी सख्त आदेशो एवं परिवहन आयुक्त के निर्देश पर पूर प्रदेश में 14 सितंबर से 19 सितंबर 2026 तक ब्लमिशन सेफ फ्यूचरह्व यानी स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। कानपुर नगर में पंजीकृत स्कूली वाहनों के स्वामियों और विद्यालय प्रबंधनों को नोटिस जारी कर मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि संस्थागत विद्यालयों के वाहनो में महिला परिचर की तैनाती होना अनिवार्य है। जिन वाहनों में छात्राओं (बालिकाओं) को लाया-ले जाया जाता है, उनमें महिला परिचर की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही सभी वाहनों के प्रपत्र (फिटनेस, परमिट आदि) वैध होने चाहिए। चालक एवं परिचर दोनों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है। परिवहन विभाग ने सभी विद्यालय प्रबंधनों, वाहन स्वामियों और चालकों से अपील की है, कि वे स्कूली बच्चों के आवागमन के दौरान यातायात व सुरक्षा नियमों का शत-प्रतिशत पालन करें।

समाधान दिवस में अफसरों को दो टूक—लापरवाही मिली तो कार्रवाई

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। तहसील तालबेहट में शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में मंडलायुक्त झांसी मंडल बिमल कुमार दुबे और जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट चेतावनी दी गई कि लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाधान दिवस में सबसे अधिक शिकायतें जमीन और राजस्व विवादों से संबंधित रहीं। मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर संबंधित मामलों में मौके पर जाकर जांच करने और निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा गया कि शिकायतों का केवल कागजी निस्तारण न किया जाए, बल्कि स्थलीय जांच के बाद समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि जमीनी और राजस्व विवादों में अनावश्यक देरी से आम लोगों को परेशानी होती है। ऐसे मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाए। जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता है।

डीएम की अध्यक्षता में सी.एम. डैश बोर्ड व सी.एम.आई. एस. की समीक्षा बैठक सम्पन्न

बहराइच। सी.एम. डैश बोर्ड पर विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों में प्राप्त ग्रेड एवं रैंक तथा सी.एम.आई.एस. की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान उपायुक्त स्वतारोजगार को निर्देशित किया गया विशेष प्रयास कर अपेक्षित प्रगति प्राप्त करते हुए रैंक व ग्रेड में सुधार लाना सुनिश्चित करें। चिकित्सा विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया गया कि डाटा फीडिंग कार्य में 20 कर्मचारियों को लगा कर पुराने डाटा फीडिंग कार्य पूर्ण कराकर आगामी 10 दिवसों में फाडिंग कार्य को अद्यतन करते हुए रैंक एवं ग्रेड में सुधार सुनिश्चित किया जाय।

फैमिली आई.डी. की समीक्षा करते हुए जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को निर्देश दिया गया कि योजना का निरन्तर अनुश्रवण करते हुए प्रगति को बढ़ाया जाय। पंचायती राज विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए डीएम द्वारा निर्देश दिया गया कि मुख्य विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी वर्चुअल माध्यम से सहायक विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा करें ताकि अपेक्षित प्रगति हासिल की जा सके। डीएम ने कहा कि आवश्यकयता पड़ने पर वे स्वयं भी वर्चुअल बैठक में प्रतिभाग करेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि सैम-मैम आंकड़ों को फीडिंग कार्य को अद्यतन रखा जाय। इसी प्रकार जिलाधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग को भी प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार धनंवता, अपर जिलाधिकारी अरूण कुमा, मुख्य राजस्व अधिकरी सौरभ दुबे, सम्बन्धित एसडीएम, तहसीलदार व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

मांगें पूरी न हुईं तो 22 से अतिरिक्त हलकों का बहिष्कार करेंगे लेखपाल

जलालाबाद में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, लंबित मांगों पर अब आर-पार की तैयारी

वेब वार्ता, रामनिवास शर्मा

जलालाबाद। लंबित मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अब आंदोलन का रुख तेज करने का ऐलान किया है। शनिवार को तहसील जलालाबाद में लेखपालों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शासन स्तर पर लंबित मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग की। लेखपालों ने चेतावनी दी कि मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो 22 सितंबर से प्रदेशव्यापी स्तर पर अतिरिक्त हलकों का बहिष्कार शुरू किया जाएगा।

ज्ञापन में लेखपालों ने कहा कि राजस्व अभिलेखों के रखरखाव से लेकर वरासत, नामांतरण, पैमाइश, ई-गवर्नेंस, आपदा प्रबंधन और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं तक का जिम्मा लेखपालों पर है। इसके बावजूद लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं। संघ ने अंतर्मंडलीय स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन विसंगति और अतिरिक्त कार्यभार सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग उठाई।

लेखपालों का कहना है कि काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है, जबकि संसाधन और मानवबल की स्थिति उसी अनुपात में नहीं बढ़ी है। ऐसे में अतिरिक्त हलकों का काम करना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। संघ ने शासन से मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष अरविंद कनौजिया, रविकांत, पवनेश कुमार, मोहन शर्मा, नीरज राठौर सहित अन्य लेखपाल मौजूद रहे। लेखपालों की चेतावनी के बाद अब प्रशासन और शासन के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने किया प्रेरणा कैन्टीन का शुभारम्भ

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। आज जिलाधिकारी अनुनय झा एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा द्वारा तहसील परिसर सण्डीला हरदोई में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत अधुना मॉडल प्रेरणा कैन्टीन ग्राम पंचायत छनोइया मलेहरा विकास खण्ड सण्डीला, हरदोई का उद्घाटन किया गया। इस कैन्टीन की स्थापना उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत की गई है। तहसील परिसर में प्रेरणा कैन्टीन से आगन्तुकों को चाय, नाश्ता, जलपान एवं शुद्ध भोजन उपलब्ध हो सकेगा, प्रेरणा कैन्टीन संचालन हेतु मिशन द्वारा रू0 200000.00 की सहायता प्रदान की जा रही है। उक्त अधुना मॉडल प्रेरणा कैन्टीन में 10 सदस्यी ए०ओ०पी० का गठन कर संचालित की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत जुड़े स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में आय की वृद्धि होने से उनके जीवन स्तर में प्रभावी सुधार सम्भावित है। इससे योजना की टैग लाइन समूह से समृद्धि की ओर की भावना धरातल पर परिलक्षित हो रही है। इस कार्यक्रम में एस०डी०एम० सण्डीला सुश्री नारायणी भाटिया (आई०ए०एस०), खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड-बेंहदर सुश्री संस्कृति त्रिवेदी (आई०ए०एस), उपायुक्त स्वतः रोजगार, निशांत राय, सी०ओ० सण्डीला श्लोक गौतम, खण्ड विकास अधिकारी सण्डीला सुश्री गौरी राठौर एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुशायरा ग्राउंड का पुराना रास्ता खोलने की मांग

मुरादाबाद, वेब वार्ता

यूथ बार एसोसिएशन मुरादाबाद ने मुशायरा ग्राउंड स्थित पुराने रास्ते को पुनः खोलने एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने बगिया को जाने वाली सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग उठाई है। यूथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद नईम एडवोकेट के नेतृत्व में जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को पेश किए गए ज्ञापन में कहा गया है कि कलेक्ट्रेट परिसर में पुराने मुशायरा ग्राउंड से लगा हुआ सैकडों वर्ष पुराना रास्ता था जिससे होकर अधिवक्तागण पुराने सिविल कोर्ट व बगिया चैम्बर्स में सुविधा पूर्वक आते जाते थे, परन्तु कुछ समय से उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया है, जिसके कारण अधिवक्ताओं को अपने चैम्बरों से काफी घूमकर पुराने सिविल कोर्टस व बगिया चैम्बर्स में आना-जाना पडता है, जिससे कारण अधिवक्तागण समय पर न्यायालयों में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जिससे अधिवक्ताओं को काफी परेशानी होती है।

नर्मदेश्वर धाम में गूंजे भक्ति के सुर, भजनों पर देर रात तक झूमे श्रद्धालु

वेबवार्ता, हरदोई

शाहाबाद क्षेत्र के गाँव गुजीदेई स्थित नर्मदेश्वर धाम में शुक्रवार की रात भक्ति और संगीत का ऐसा संगम बना कि समय का अहसास ही मिट गया। ढोलक की थाप पर थिरकते कदम, हारमोनियम से निकलते मधुर सुर और भजनों में डूबी आवाजों ने मंदिर परिसर को देर रात तक भक्तिरस में सराबोर रखा। भजन शुरू हुए तो श्रद्धालु महज श्रोता नहीं रहे, बल्कि सुरों के साथ स्वयं भक्ति के रंग में रंगते चले गए।

नर्मदेश्वर धाम महादेव मंदिर में आयोजित भजन संध्या का आयोजन वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकान्त पाठक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से भजन-कीर्तन का आनंद लिया और भगवान नर्मदेश्वर महादेव की आराधना की।भजन संध्या में वाके लाल ने ढोलक पर लयकारी से माहौल में उत्साह भरा, जबकि बाबू खां और महेश ने हारमोनियम पर मधुर सुरों की संगत की। ढोलक और हारमोनियम की जुगलबंदी के बीच भजनों की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कई श्रद्धालु भक्ति में भाव-विभोर होकर झूमते नजर आए।

...तस्वीर भी प्रस्तुत की

आयोजन ने ग्रामीण अंचल की सामूहिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा की खूबसूरत तस्वीर भी प्रस्तुत की। समापन पर श्रद्धालुओं ने नर्मदेश्वर महादेव के चरणों में शीश नवाकर क्षेत्र की सुख-शांति, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की।इस अवसर पर राम नारायण गुप्ता, रामकिशोर गुप्ता, उमेश चंद्र त्रिवेदी, प्रच्छित पाठक, शरदेंदू पाठक,हिमांशू पाठक, सुशील कुमार पाठक बरगदिया से महेश राजपूत, कुलदीप, महेंद्र पाल, गिरिद राजपूत, जागेश्वर और लाला राम, परेली से राजेश्वर, रघुराई, अनमोल नन्हे सक्सेना और ओमनिवास पाठक तथा सूरापुर से वाके लाल, शिशुपाल और खियासी समेत क्षेत्र के अनेक लोगों ने सहभागिता की।

टीएमसी उम्मीदवार की नाम वापसी के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान गिरफ्तार

ममता बनर्जी ने किया था कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में शुक्रवार को घटनाक्रम तेजी से बदला। कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को एक पुराने हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।

खास बात यह है कि ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ही नंदीग्राम में अपने गुट के उम्मीदवार के चुनाव मैदान से हटने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को समर्थन देने का ऐलान किया था। गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद नंदीग्राम का चुनावी मुकाबला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान के खिलाफ पुराने हत्या मामले में कार्रवाई की गई है। कुछ रिपोर्टों में उनके खिलाफ पहले से वारंट जारी होने की बात भी कही गई है। इससे पहले ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट की नंदीग्राम उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसके बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की कि उनका गुट नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेगा और अपना कोई प्रत्याशी चुनाव में नहीं उतारेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला विपक्षी एकजुटता और इंडिया गठबंधन के हित में लिया गया है।

संचिता ने सीएम से की थी मुलाकात

संचिता प्रधान डे ने नामांकन वापस लेने से पहले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से नबन्ना में मुलाकात की थी। इसके बाद उनके चुनाव मैदान से हटने का ऐलान कर दिया गया। हालांकि, उनके नामांकन वापस लेने की वजह को लेकर उनकी ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

टीएमसी नाम-सिंबल विवाद के बीच बढ़ी हलचल

नंदीग्राम का बदलता घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जबकि टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर भी विवाद चल रहा है। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव के लिए अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए, टीएमसी के पुराने नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाने का विरोध किया है। ममता ने कहा आयोग का फैसला अंतिम नहीं है और उनकी पार्टी इसे कानूनी तौर पर चुनौती देगी।

यहां बताते चलें कि नंदीग्राम सीट पर भाजपा ने हसीरानी रथ को उम्मीदवार बनाया है, जबकि ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट भी मैदान में है। नंदीग्राम में 6 अक्टूबर को मतदान होना है। कांग्रेस ने मिलन प्रधान को अपना उम्मीदवार बनाया था। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके चुनाव प्रचार और आगे की चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

निठारी कांड से बरी सुरेंद्र कोली ने हरिद्वार में फांसी लगाकर की आत्महत्या

हरिद्वार। निठारी हत्याकांड के मामलों में अदालतों से बरी हो चुके सुरेंद्र कोली की हरिद्वार में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, उसने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की। उसका शव शुक्रवार सुबह सप्तसरोवर रोड स्थित लाल माता मंदिर के पास चाय की दुकान में मिला। कोली पिछले कुछ महीनों से हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में रहकर चाय की दुकान चला रहा था।

स्थानीय लोगों ने दुकान के भीतर शव लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उसके परिवार को भी घटना की जानकारी दी गई है।

2025 में सुप्रीम कोर्ट से मिली थी अंतिम राहत

निठारी हत्याकांड दिसंबर 2006 में सामने आया था, जब नोएडा के निठारी में कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे नाले से बच्चों के कंकाल और अन्य अवशेष मिले थे। मामले में पंढेर के घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली को आरोपी बनाया गया था।

अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोली को निठारी से जुड़े 12 मामलों में बरी कर दिया था। इसके बाद इन फैसलों को चुनौती देने वाली सीबीआई और पीड़ित परिवारों की 14 अपीलों को सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2025 में खारिज कर दिया।

हालांकि, उस समय कोली एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा के कारण जेल में था। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उस अंतिम मामले में भी उसकी दोषसिद्धि रद्द कर दी और रिहाई का आदेश दिया। इसके बाद वह जेल से बाहर आया था। हरिद्वार पुलिस अब कोली की मौत के कारणों और परिस्थितियों की जांच कर रही है।

चीन में हवा में उल्टी लटककर तेज दौडती है सस्पेंडेड मोनोरेल

बीजिंग। चीन के वुहान प्रांत में चलने वाली एक सस्पेंडेड मोनोरेल जमीन पर बिछी पटरी पर दौड़ने के बजाय ऊपर बने गाइडवे से नीचे की ओर लटकी रहती है। इस सस्पेंडेड मोनोरेल को ऑप्टिक्स वैली स्काईरेल और ऑप्टिक्स वैली फोटॉन के नाम से जाना जाता है। ट्रेन के अंदर बैठने वाले यात्रियों को कांच के फर्श और बड़ी खिड़कियों के जरिए नीचे का नजारा दिखाई देता है, जिससे सफर रोमांच और डर का अनोखा अनुभव बन जाता है। इसका डिजाइन पारंपरिक ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। इसमें ट्रैक जमीन के नीचे या सामान्य पिलर के ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर की तरफ बने एक मजबूत गाइडवे के रूप में तैयार किया गया है। ट्रेन का ऊपरी हिस्सा स्टील और कंक्रीट से बने सिंगल बीम से जुड़ा रहता है। बाहर से देखने पर ट्रेन हवा में उल्टी लटकी हुई नजर आती है, लेकिन इसका ढांचा विशेष रूप से इसी तरह के संचालन के लिए तैयार किया गया है। ट्रेन में रबर के पहियों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यात्रा के दौरान शोर कम होता है और संचालन अपेक्षाकृत सहज रहता है। फिलहाल इसमें दो डिब्बों का ट्रेन सेट चलाया जा रहा है, जिसमें करीब 220 यात्री सफर कर सकते हैं।

बांग्लादेश की तारिक सरकार धमकियां देने पर उतरी

अगर भारत को संबंध सुधारने हैं तो शेख हसीना की वापसी जरूरी शर्त

नई दिल्ली। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार धमकियों पर उतर आई है। ढाका ने अब भारत को आंख दिखाते हुए कहा कि अगर संबंध सुधारने हैं तो शेख हसीना की वापसी जरूरी शर्त है। बांग्लादेश ने पूर्व पीएम शेख हसीना और अवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादर समेत कई नेताओं के प्रत्यर्पण की मांग रखी है। बांग्लादेश में जुलाई 2023 में हुए हिंसक छात्र आंदोलन के बाद तत्कालीन पीएम शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थी तब से यहीं रह रही हैं। इसके बाद तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद से ही बांग्लादेश कई मौकों पर भारत से शेख हसीना की वापसी की मांग की है। इस पूरे मामले पर भारत सरकार का कहना है कि वह तय कानूनों की जांच के बाद ही सोच समझकर फैसला लेगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना को उनके ही देश में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। उन पर छात्र आंदोलन में दमन के आरोप लगे हैं और हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना गया है। इसके बावजूद शेख हसीना ने कहा कि वह अपने देश लौटना चाहती हैं। भारत में शरण लेने के बाद पहली बार बीते महीने शेख हसीना ने मीडिया से बातचीत की थी। बातचीत में शेख हसीना ने कहा कि वे आवामी लीग के अन्य नेताओं के साथ दिसंबर में बांग्लादेश जा सकती हैं। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की जनता फैसला करेगी कि वह अपराधी हैं या नहीं। इससे पहले ही बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान के सूचना एवं प्रसारण मामलों के सलाहकार जाहेद उर रहमान ने भारत के सामने शर्त रख दी है।

रहमान ने कहा कि शेख हसीना और अवामी लीग के अन्य नेताओं का प्रत्यर्पण ही रिश्ते सुधारने के लिए अहम शर्त है।

कश्मीर में दशकों पुरानी है अमेरिका की दिलचस्पी

खुफिया रिपोर्टों से हुआ खुलासा

नई दिल्ली। आज भले ही अमेरिका कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला बताता है, लेकिन लगभग सात दशक पहले हालात जुदा थे। 1950 के दशक की शुरूआत में, कश्मीर अमेरिका के लिए सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद नहीं था। शीत युद्ध के दौरान, अमेरिका मध्य और दक्षिण एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र मानता था। हाल ही में सामने आए अमेरिकी दस्तावेजों और खुफिया रिपोर्टों से इसका खुलासा होता है कि कैसे अमेरिका की कश्मीर में गहरी दिलचस्पी थी, और इसकी भौगोलिक स्थिति तथा कई देशों से लगी सीमाओं के कारण यह इलाका वाशिंगटन की नजर में क्यों महत्वपूर्ण था।

1951 की अमेरिकी खुफिया रिपोर्टें वहां के अधिकारियों, जैसे फ्रैंक कॉलिन्स, हॉवर्ड मेयर्स और मिस्टर मैफेट के बीच हुई कश्मीर को लेकर बातचीत का ब्यौरा देती हैं। इन रिपोर्टों में कॉलिन्स और मैफेट को पाकिस्तान और ब्रिटेन की ओर झुकाव रखने वाला और भारत का आलोचक बताया गया है, जबकि हॉवर्ड मेयर्स को एक अधिक संतुलित अधिकारी के रूप में दिखाया गया है। जनवरी 1951 के गोपनीय अमेरिकी ज्ञापन में कश्मीर विवाद पर ब्रिटेन और अमेरिका की रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें अमेरिका ने ब्रिटेन से पहल करने का आग्रह किया था। इन दस्तावेजों में भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गतिविधियों और प्रस्तावित संविधान सभा को लेकर चिंता जाहिर की गई थी, जिसके प्रस्ताव को अक्टूबर 1950 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पारित किया था और पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था।

दस्तावेजों में जनमत संग्रह का जिक्र है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि यदि अमेरिका और ब्रिटेन पाकिस्तान पर सैनिकों, नागरिकों और कबायली लड़ाकों को वापस बुलाने का दबाव डालें और आजाद कश्मीर फोर्स को खत्म किया जाए, तब जनमत संग्रह संभव हो सकता है। दूसरी ओर, भारत का तर्क था कि पाकिस्तान की सेना और घुसपैठियों की वापसी पहले होनी चाहिए। यह मूल मतभेद ही इस मुद्दे को सुलझने नहीं दे रहा था।

खुफिया दस्तावेज शेख अब्दुल्ला और तत्कालीन अमेरिकी राजदूत लॉय हेंडरसन की बातचीत का उल्लेख करते हैं। अब्दुल्ला ने आजाद कश्मीर (स्वतंत्र कश्मीर) देखने की इच्छा व्यक्त कर कहा कि कई कश्मीरी भी ऐसा चाहते थे। उनका मानना था कि एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे रिश्ते आवश्यक है।

आस्था और रोमांच का अद्भुत संगम है ढोलकल गणेश मंदिर

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले की बैलाडीला पहाड़ियों के बीच लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ढोलकल गणेश मंदिर एक रहस्यमयी स्थान है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां सैकडों फीट उंची पहाड़ी की दुर्गम चोटी पर विराजमान भगवान गणेश की यह प्राचीन प्रतिमा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को घने जंगलों तथा चुनौती भरे पहाड़ी रास्तों से होकर यहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। ढोलकल गणेश की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ मौजूद प्राचीन प्रतिमा है, जो इसकी ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्ता को दशार्ती है। उपलब्ध पुरातात्विक जानकारी के अनुसार, करीब तीन फीट ऊंची यह प्रतिमा एक ही विशाल ग्रेनाइट पत्थर को बड़ी कुशलता से तराशकर बनाई गई है। इसका निर्माण छिंदक नागवंश के शासनकाल से जोड़ा जाता है और माना जाता है कि इसे 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच निर्मित किया गया था। भगवान गणेश यहाँ ललितासन मुद्रा में विराजमान हैं, जो उनकी आरामदायक और राजसी स्थिति को दशार्ती है।

प्रतिमा के चार हाथों में फरसा, टूटा हुआ दंत, मोदक और माला जैसे विशिष्ट प्रतीक दिखाई देते हैं, जो उनकी पौराणिक पहचान का हिस्सा हैं। ढोलकल पहाड़ी से भगवान गणेश और महर्षि परशुराम से जुड़ी एक स्थानीय पौराणिक मान्यता भी जुड़ी हुई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसी क्षेत्र में इन दोनों महान हस्तियों के बीच युद्ध हुआ था। लोककथाओं के अनुसार, इस युद्ध के दौरान महर्षि परशुराम के फरसे के प्रहार से भगवान गणेश का एक दांत टूट गया था। इसी घटना के कारण भगवान गणेश को एकदंत के नाम से भी जाना जाता है। यह कथा स्थानीय धार्मिक परंपरा और आस्था का अभिन्न अंग है, जो इस स्थान को और भी पवित्र बनाती है। ढोलकल मंदिर की यात्रा का सबसे रोमांचक और यादगार हिस्सा निश्चित रूप से यहाँ तक पहुँचने का दुर्गम रास्ता है। दंतेवाड़ा के फरसपाल गांव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में घना जंगल, ऊबड़-खाबड़ पगडंडियां, चट्टानी रास्ते और पहाड़ी क्षेत्र के प्राकृतिक नजारे देखने को मिलते हैं, जो इस ट्रेक को और भी खास बना देते हैं। चोटी की ओर बढ़ते हुए आसपास का प्राकृतिक वातावरण मन को मोह लेता है। पहाड़ी के शीर्ष पर पहुँचने के बाद, बस्तर के विशाल जंगलों और आसपास की पहाड़ियों का विस्तृत और मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। हरियाली और शांत वातावरण के बीच स्थापित यह प्राचीन प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए एक गहरे आस्था का केंद्र है, जहाँ पहुँचकर भक्त शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। ढोलकल गणेश तक पहुँचने के लिए सबसे पहले दंतेवाड़ा या जगदलपुर से फरसपाल गांव तक पहुँचा जा सकता है। इसके बाद की यात्रा पैदल करनी होती है। पहाड़ी रास्ते और जंगली क्षेत्र को देखते हुए, स्थानीय परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी लेकर यात्रा करना और आवश्यकतानुसार स्थानीय गाइड की सहायता लेना अत्यंत उपयोगी रहेगा।

जलवायु परिवर्तन से एंटीबायोटिक दवाओं पर मंडरा रहा संकट

वाशिंगटन। धरती के बढ़ते तापमान और बदलते मौसम के कारण कुछ संक्रामक रोग उन इलाकों तक पहुंच सकते हैं, जहां पहले उनका प्रकोप बेहद कम था। इसके अलावा कुछ परिस्थितियां ऐसे बैक्टीरिया के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकती हैं, जिन पर सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन का असर अब केवल मौसम, बारिश और तापमान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका संबंध संक्रामक बीमारियों और एंटीबायोटिक प्रतिरोध से भी जुड़ता जा रहा है।

सपा तीन-तिकड़म के बावजूद भी बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा सकी

यूपी में बीजेपी की हैट्रिक तय, फिर खिलेगा कमल

नई दिल्ली। यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मौर्य का ट्वीट बीजेपी नेता प्रोफेसर रामाश्रय कुशवाहा के सपा में शामिल होने के बाद सामने आया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर अखिलेश को साल 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान की उनकी रणनीति की याद दिलाई।

मौर्य ने चुटकी लेते हुए कहा कि तीन-तिकड़म के बावजूद सपा बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा सकी। इस बार भी उनकी सभी रणनीति और जातीय समीकरण फेल होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की हैट्रीक जीत का दावा भी कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में 2022 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए लिखा- उस समय सपा ने राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के साथ गठबंधन किया था और कई वजूद वाले नेताओं को अपने दल में शामिल कराया था। इसके बावजूद वह बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा सकी थी। सपा के सभी सामाजिक और राजनीतिक समीकरण धरे के धरे रह गए थे।

केशव ने लिखा- सपा के पास न कोई दृष्टिकोण है और न विश्वसनीय नेतृत्व। जनता का भरोसा तो उसमें कतई नहीं है इसलिए इस बार भी उसका जातीय समीकरणों और खोखले नारों का खेल धरा का धरा रह जाएगा। उन्होंने अपने पोस्ट के अंत में लिखा- कुल मिलाकर लब्बोलुआब यह है कि सपा के अखिलेश यादव की कोई भी पैंतरेबाजी तीसरी बार भी बीजेपी की बाजी पलट नहीं पाएगी। यूपी में बीजेपी की हैट्रिक तय है और तीसरी बार भी कमल ही खिलेगा।

केशव प्रसाद मौर्य का ये पोस्ट ऐसे समय में सामने आया है जब बीजेपी के नेता और 6 बार के मंत्री रहे प्रोफेसर रामाश्रय कुशवाहा सपा में शामिल हो गए हैं। 2013 में कुशवाहा ने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। कुशवाहा के अलावा रालोद, बसपा, निषाद पार्टी, लेखपाल संघ, अपनादल और एआईएमआईएम समेत अलग-अलग संगठनों से जुड़े स्थानीय नेताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की है।

सिंधु संधि पर भारत का फैसला पाक प्रायोजित आतंकवाद के जवाब में जायज कदम

यूएन मानवाधिकार परिषद में अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं ने संधि निलंबित को सही ठहराया

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र में आयोजित कॉन्फ्रेंस में अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं ने दिल्ली के सिंधु जल संधि को निलंबित करने को सही ठहराया।

गुरुवार को इस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि भारत का यह फैसला दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उसकी बदनीयती के जवाब में जायज कदम था। यह पाकिस्तान के लिए एक झटका है क्योंकि उसकी कोशिश इस मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचने की है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को सिंधु प्रणाली की नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर हस्ताक्षर किए गए थे। बीते साल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को निलंबित कर दिया था। भारत ने इस कदम के पीछे का मकसद पाकिस्तान के आतंक को समर्थन देना बताया है। सामुदायिक जल अधिकार और सिंधु जल संधि को स्थगित रखने की जरूरत विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ब्रुसेल्स स्थित साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम के रिसर्च डायरेक्टर सीगफ्राइड वुल्फ ने कहा कि भारत को 1960 की संधि की समीक्षा की मांग करने का पूरा अधिकार है। ये जायज है क्योंकि पाकिस्तान के व्यवहार ने संधि की प्रस्तावना में बताए गए समझौते के मकसद, उद्देश्य और भावना को कमजोर किया है।

वुल्फ ने इस संधि को भारत की तरफ से दी गई एक स्वैच्छिक रियायत बताया जो एक संरचनात्मक असंतुलन पर आधारित थी। उन्होंने पाकिस्तान के उस दावे को इंजीनियरिंग मिथक करार दिया, जिसमें उसने कहा है कि भारत नदियों के बहाव को रोक रहा है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी नदियों पर बनी भारतीय परियोजनाएं पानी की खपत नहीं करतीं और पानी को आगे भेजने से पहले बिजली पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद का अभियान भारत के विकास में देरी करने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे बदनाम करने और पानी के उस संकट से ध्यान भटकाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जो पूरी तरह से खुद पैदा किया गया है। इसकी जड़ें पंजाब के दबदबे, सामंती जमींदारी व्यवस्था, शहरी झुकाव और नहरों के खस्ताहाल बुनियादी ढांचे में हैं।

लंदन में रहने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ आजकिया ने कहा कि पानी का अधिकार एक बुनियादी मानवाधिकार है। इससे पाकिस्तान के सैन्य तंत्र ने सिंध को वंचित रखा है। सिंध में कोट्री के पास सिंधु नदी का बहाव ऊपर की ओर नहरों के जरिए पानी मोड़े जाने के कारण बहुत कम हो गया है। भारत में हुए बड़े आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का 65 साल पुराने समझौते को निलंबित करने का फैसला सही था। एक भारतीय एनजीओ ने तर्क दिया कि इस क्षेत्र में पानी की सुरक्षा से जुड़ी बदलती स्थितियों को देखते हुए 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते का आज के मानवाधिकारों के नजरिए से फिर से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

एनजीओ ने कहा कि सिंधु संधि लंबे समय से चले आ रहे अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक अहम उदाहरण होने के बावजूद छह दशक में पानी की सुरक्षा से जुड़े हालात बदल गए हैं। इसमें आबादी में बढ़ोतरी, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों के पीछे हटने, भूजल के कम होने और नदियों के बहाव में लगातार अनिश्चितता जैसे कारण हैं।

विकास की नई रफ्तार से बदल रहा छत्तीसगढ़ को मिल रही मजबूती: अरुण साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विकास का दायरा तेजी से बड़ रहा है। राज्य की अधोसंरचना को नई मजबूती दी जा रही है। सड़क, परिवहन और कनेक्टिविटी से लेकर आवास, जलापूर्ति और सार्वजनिक परिवहन तक के लिए आने वाले समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास की आधारभूत संरचना तैयार की जा रही है। मजबूत अधोसंरचना आर्थिक विकास की बुनियाद है और राज्य सरकार इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अधोसंरचना विकास पर अब तक 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज 'विकसित छत्तीसगढ कॉन्क्लेव-2026' में ये बातें कहीं। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नवा रायपुर में इकोनॉमिक टाइम्स ग्रुप द्वारा आयोजित 'छत्तीसगढ कॉन्क्लेव-2026' के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ तेजी से आगे बड़ रहा है। विकास की इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए राज्य में अधोसंरचना के विस्तार पर लगातार काम किए जा रहे हैं। बेहतर सड़कें, सुगम परिवहन और मजबूत कनेक्टिविटी न केवल लोगों की आवाजाही को आसान बनाती हैं, बल्कि उद्योग, व्यापार और निवेश के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश समावेशी विकास की दिशा में आगे बड़ रहा है। केंद्र सरकार उन राज्यों और क्षेत्रों की विकास संबंधी जरूरतों पर भी विशेष ध्यान दे रही है, जो लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा में अपेक्षाकृत पीछे रहे हैं। श्री साव ने विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां कनेक्टिविटी, अधोसंरचना और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे देश के अलग-अलग हिस्सों के बीच विकास का संतुलन मजबूत हो रहा है और दूरस्थ क्षेत्रों को भी व्यापक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के अवसर बड़ रहे हैं। श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास का लाभ अधिक से अधिक क्षेत्रों और लोगों तक पहुंचाने के लिए अधोसंरचना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। तेजी से बड़ते शहरीकरण और शहरों की बड़ती आबादी के साथ लोगों की जरूरतें भी बदल रही हैं। ऐसे में केवल वर्तमान जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शहरी सुविधाओं और अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रगति के लिए मजबूत अधोसंरचना जरूरी है। स?कों और परिवहन सुविधाओं के विस्तार से कनेक्टिविटी बेहतर होती है और इसका सीधा लाभ आर्थिक गतिविधियों को मिलता है। छत्तीसगढ़ में इसी दृष्टि से अधोसंरचना विकास को विकास की गति से जोड़ते हुए काम किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक श्री नीलेश महादेव क्षीरसागर ने कहा कि तेजी से ब?ते शहरीकरण के साथ शहरों की जरूरतों का स्वरूप भी बदल रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक शहरी अधोसंरचना तैयार की जा रही है।

ताजा खबर
संक्षिप्त

इंद्रेश महाराज करेंगे भागवत कथा 21 से 2 तक होगी कृषि उपज मंडी ग्राउंड में कथा का आयोजन

रायपुर। रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित कृषि उपज मंडी ग्राउंड में 21 से 27 सितंबर तक श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा का शुभारंभ 21 सितंबर सोमवार को सुबह 11 बजे श्रीराम मंदिर कृषि उपज मंडी से कलश यात्रा के साथ होगा। इसके बाद दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कथा होगी। कथा वाचन इंद्रेश उपाध्याय करेंगे। 21 सितंबर को कथा का शुभारंभ होगा। 22 सितंबर को ध्रुव चरित्र का वर्णन किया जाएगा, जिसमें भक्त ध्रुव की भक्ति और भगवान की कृपा का प्रसंग रहेगा। 23 सितंबर को प्रह्लाद चरित्र के माध्यम से भगवान की कृपा और भक्त प्रह्लाद की भक्ति का वर्णन होगा। 24 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव प्रसंग होगा, जिसमें भगवान के नाम स्मरण की महिमा बताई जाएगी। 25 सितंबर को श्री गोवर्धन लीला महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और गोवर्धन पर्वत की कथा का वर्णन किया जाएगा। 26 सितंबर को श्रीकृष्ण-रुक्मिणी महोत्सव होगा। जिसमें भक्ति, प्रेम और भगवान की करुणा का प्रसंग रहेगा। कथा के दौरान प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक श्रद्धालु कथा का श्रवण कर सकेंगे। 27 सितंबर रविवार को कथा विश्राम और पूर्णाहुति होगी। इस दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आरती, महाप्रसादी वितरण और आशीर्वचन का कार्यक्रम रखा गया है। आयोजन के लिए कृषि उपज मंडी ग्राउंड में तैयारियां की जा रही हैं। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है।

एमपी में 1.45 लाख साल के पेड़ों पर चली आरी

रायपुर। मध्यप्रदेश के जंगलों में साल के पेड़ों पर बोरर कीट के बड़े प्रकोप के बाद अब छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने भी निगरानी बढ़ा दी है। प्रदेश के साल बहुल वन क्षेत्रों में बोरर की स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वे शुरू किया गया है। विभागीय टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पेड़ों की स्थिति और कीट के संभावित संक्रमण की निगरानी कर रही हैं। संक्रमण मिलने पर स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर कीटनाशक के इस्तेमाल के साथ संक्रमित पेड़ों की कटाई का विकल्प भी अपनाया जा सकता है। मध्यप्रदेश में स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्रों में बोरर के प्रकोप के बाद करीब 1.45 लाख साल के पेड़ों की कटाई को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ में साल बोरर का खतरा नया नहीं है। कोरबा वन मंडल के बालको क्षेत्र में 2022-23 के दौरान करीब 1,200 साल के पेड़ों को बोरर से प्रभावित पाया गया था। विभाग ने दवा का छिड़काव करने के साथ पेड़ों के उन हिस्सों को भी उपचारित किया, जहां से कीट के प्रवेश के संकेत मिले थे। इसके बावजूद संक्रमण को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सका। बाद में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद 923 प्रभावित पेड़ों की कटाई का रास्ता साफ हुआ। विज्ञानी अध्ययनों में भी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के साल वनों में बोरर के प्रकोप का उल्लेख मिलता है।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने ली समय-सीमा फॉलो-अप बैठक

रायपुर। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जिले के विभिन्न विभागों की समय-सीमा फॉलो-अप बैठक ली। बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और जन शिकायतों के निराकरण की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि आने वाले दिनों में रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर, समस्या समाधान शिविर जैसे आयोजन किए जाएंगे, जिसमें पूरा जिला प्रशासन समन्वय बनाकर कार्य करेगा। कलेक्टर ने नगर निगम को निर्देशित करते हुए कहा कि शहर में लगे वाटर एटीएम को दुरुस्त किया जाए, ताकि आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि राजधानी में कई स्थानों पर पैनिक बटन खराब होने की जानकारी मिली है, इसे पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम समन्वय बनाकर दुरुस्त करें, ताकि महिलाएं आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोग कर सकें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जो शासकीय इमारतें जर्जर हो गई हैं, उनका सर्वे कर उन्हें ध्वस्त करने की कार्यवाही की जाए।

सेमीकंडक्टर से ग्रीन एनर्जी तक, भविष्य के उद्योगों का नया गंतव्य बन रहा छत्तीसगढ़

भविष्य के उद्योगों का नया केंद्र बनने की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित तीन दिवसीय 'इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर-2026' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों से आए उद्यमियों, निवेशकों और औद्योगिक प्रतिनिधियों का छत्तीसगढ़ की धरती पर स्वागत करते हुए उन्हें प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने और यहां उपलब्ध निवेश की व्यापक संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज अपनी पारंपरिक औद्योगिक ताकत के साथ नई अर्थव्यवस्था और उभरते उद्योगों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खनिज, ऊर्जा, वन संपदा, पर्याप्त मानव संसाधन और देश के मध्य में अनुकूल भौगोलिक स्थिति हमारी स्वाभाविक ताकत है। राज्य सरकार इन खूबियों को आधुनिक तकनीक, बेहतर अधोसंरचना और निवेशक हितैषी नीतियों से जोड़कर छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख औद्योगिक एवं निवेश गंतव्यों में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की भूमिका केवल उद्योगों के लिए नियामक की नहीं है। हम सरकार को उद्योग और निवेश की राह आसान करने वाले सहयोगी और 'एक्सीलरेटर' के रूप में विकसित कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि निवेश का प्रस्ताव आने से लेकर उद्योग के धरातल पर स्थापित होने तक हर चरण में निवेशकों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था मिले। मुख्यमंत्री ने लघु उद्योग भारती द्वारा राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण औद्योगिक आयोजन के लिए रायपुर का चयन किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई का विस्तार होने से स्थानीय स्तर पर उद्यमिता बढ़ती है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का लाभ समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु उद्योग भारती देशभर के 750 से अधिक जिलों में उद्यमियों को संगठित कर उद्योग और उद्यमिता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में भी 1200 से अधिक लघु एवं मध्यम उद्योग संगठन से जुड़े हैं। 18 से 20 सितम्बर तक आयोजित इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में देशभर के 300 से अधिक एमएसएमई उद्यमियों की भागीदारी इस आयोजन के महत्व को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह औद्योगिक मेला केवल उत्पादों और तकनीकों की प्रदर्शनी नहीं है। यह उद्यमियों के बीच संवाद, अनुभव, नवाचार और तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण मंच है। इसके माध्यम से नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे, नई संभावनाओं पर चर्चा होगी और युवाओं को उद्योग तथा उद्यमिता की दुनिया को करीब से समझने का अवसर मिलेगा। 'नई औद्योगिक नीति से निवेश को मिली नई गति' मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्योग जगत, निवेशकों और विभिन्न हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की है। इस नीति का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि ऐसा औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करना है, जिसमें निवेश, उत्पादन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था एक साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति में प्रक्रियाओं के सरलीकरण, निवेशकों को प्रोत्साहन, नए एवं उभरते सेक्टरों को बढ़ावा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। नीति लागू होने के बाद प्रदेश को बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

पीडब्ल्यूडी में 1 से नया टेंडर सिस्टम, नई निविदाएं अब GePNIC पर

रायपुर। लोक निर्माण विभाग में ई-टेंडरिंग की व्यवस्था अब नए सरकारी पोर्टल ळमच्छप्ब् पर शिफ्ट होने जा रही है। 1 अक्टूबर 2026 से विभाग की सभी नई निविदाओं का सृजन और प्रकाशन Government e-Procurement-NIC GePNIC के माध्यम से होगा। निविदा जारी करने से लेकर उसके मूल्यांकन और आगे की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया इसी पोर्टल पर पूरी की जाएगी। विभाग ने नई व्यवस्था शुरू होने से पहले सभी ठेकेदारों और विभागीय अमले को जरूरी तकनीकी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। नई निविदाओं में भाग लेने वाले ठेकेदारों के लिए) कराना जरूरी होगा।

विभाग ने ठेकेदारों को समय रहते पोर्टल पर नामांकन कराने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किया है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ ही ठेकेदार संघ के अध्यक्ष श्री वीरेश शुक्ला और श्री रूपेश सिंघल को पत्र भेजकर ठेकेदारों तक नई व्यवस्था की जानकारी पहुंचाने और उन्हें नामांकन के लिए प्रेरित करने को कहा है। नई व्यवस्था में सिर्फ टेंडर प्रकाशित करना ही नहीं, बल्कि निविदा की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ळमच्छप्ब् पर होगी। इसमें निविदा का सृजन, प्रकाशन, बिड प्राप्ति, तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन सहित संबंधित कार्यवाहियां शामिल हैं। विभाग ने अंतिम समय में तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए ठेकेदारों को पोर्टल पर नामांकन की प्रक्रिया पहले ही पूरी करने के निर्देश दिए हैं। पुराने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर 30 सितम्बर 2026 तक प्रकाशित निविदाओं की बिड प्राप्ति, मूल्यांकन, स्वीकृति और अन्य लंबित ऑनलाइन कार्यवाही 31 मार्च 2027 तक पुराने पोर्टल पर पूरी की जाएंगी। इसके बाद वर्तमान ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर किसी तरह की निविदा संबंधी कार्यवाही नहीं होगी। विभागीय स्तर पर भी नई व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी निविदा आमंत्रण अधिकारियों, तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन समिति के सदस्यों तथा संबंधित कर्मचारियों को यूजर आईडी बनवाने, रोल मैपिंग और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दष्ठस्ष्ट्र की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था 1 अक्टूबर से ही बिना किसी तकनीकी या प्रशासनिक अड़चन के सुचारू व प्रभावी तरीके से काम करना शुरू कर दें। पीडब्ल्यूडी में टेंडर प्रक्रिया के इस बदलाव के साथ ठेकेदारों को पुराने पोर्टल के बजाय त्द्रक्क्ष्ठ्र को नए निविदा प्लेटफॉर्म के रूप में अपनाना होगा। विभाग ने अधिकारियों और ठेकेदारों से नई व्यवस्था की तैयारी निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने को कहा है। ताकि 1 अक्टूबर से सभी नई निविदाएं निर्बाध रूप से नए पोर्टल पर संचालित की जा सकें।

छत्तीसगढ़ में 400 से ज्यादा प्राध्यापकों की पेंशन बंद, बहाली की मांग की

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 सितम्बर 2026 को एक आदेश जारी कर प्रदेश के अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों से सेवानिवृत हुए 400 से अधिक प्राध्यापकों और तृतीय व चतुर्थ कर्मचारियों की पेंशन अचानक बंद कर उनके समक्ष उनके जीवन-यापन, अपने इलाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है द्य इसी अनुक्रम में, राज्य सरकार के 11 सितम्बर 26 को जारी आदेश के अनुसार इन अनुदानित अशासकीय महाविधालयों में वर्तमान में कार्यरत प्राध्यापकों एवं तृतीय व चतुर्थ कर्मचारियों की पेंशन व ग्रेच्युटी की पात्रता व प्रावधान को अचानक सेवावधि के बीच में ही समाप्त कर दिया है द्य इससे वर्त्तमान में कार्यरत प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत होने पर जीवन-यापन की समस्यायों से जूझना होगा। राज्य सरकार अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों व कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पेंशन व ग्रेच्युटी का निरंतर भुगतान गत 37 वर्षों से करती आ रही है। 26 अक्टूबर 2010 को डॉ रमन सिंह की सरकार ने इन प्राध्यापकों व कर्मचारियों की मांग पर पांचवें वेतनमान में पेंशन तथा चौथे वेतनमान में ग्रेच्युटी देना आरम्भ किया। तब से सेवानिवृत प्राध्यापक व कर्मी पांचवें वेतनमान में निरंतर पेंशन प्राप्त करते रहे हैं । हालांकि पेंशनर्स की यह मांग थी कि शासकीय महाविद्यालयों के पेंशनर्स के समकक्ष जो जिस वेतनमान में सेवानिवृत हो रहा है, उसे उसी वेतनमान में पेंशन व ग्रेच्युटी प्रदान की जाए। वेतनमान के अनुरूप पेंशन व ग्रेच्युटी के अधिकार को लेकर उच्च न्यायालय में 80 से अधिक सेवानिवृत्त प्राध्यापकों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने अलग अलग निर्णयों में राज्य सरकार को आदेश दिया कि जो प्राध्यापक जिस वेतनमान में सेवानिवृत हुआ है, उसे उसी वेतनमान में पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए ।

श्री मुनि सुब्रत नाथ दिगंबर जैन मंदिर, उत्तम शौच धर्म मनाया गया

रायपुर। दिगंबर जैन समाज का पावन दस दिवसीय दशलक्षण महापर्व के चतुर्थ दिवस पर कचना स्थित अमलतास कैसल परिसर के 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 'उत्तम शौच धर्म' की आराधना श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ की गई। इस अवसर पर श्रीजी को पाण्डुक शिला पर विराजित कर अभिषेक एवं शांतिधारा की गई। नित्य पूजन के पश्चात श्रद्धालुओं ने दस लक्षण विधान की,उपरोक्त अवसर पर श्री कमल जैन विपिन जैन एवं अजित हर्षित जैन परिवार को शांति धारा करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ.
महापर्व के अंतर्गत रात्रि 7ः30 बजे से वीरा महिला मंडल के तत्वावधान में संगीतमय श्रीजी की आरती का आयोजन किया गया। इसके पश्चात जैन धर्म से संबंधित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

50 से अधिक सर्जन और चिकित्सकों ने आधुनिक सर्जिकल तकनीकों को देखा

बालको मेडिकल सेंटर ने किया स्तन कैंसर की लाइव सर्जरी का डेमोन्स्ट्रेशन आयोजन

रायपुर। मध्य भारत में कैंसर उपचार के प्रमुख केंद्र बालको मेडिकल सेंटर (बीएमसी) ने रायपुर में चौथे वार्षिक छत्तीसगढ़ कैंसर कॉन्क्लेव का शुभारंभ स्तन संरक्षण और स्तन पुनर्निर्माण की लाइव सर्जिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ किया। इस दौरान देशभर से आए 50 से अधिक सर्जन और चिकित्सकों ने आधुनिक सर्जिकल तकनीकों को देखा और स्तन कैंसर के उपचार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। लाइव सर्जिकल डेमोन्स्ट्रेशन का नेतृत्व मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल अस्पताल की सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. शलाका जोशी, प्लास्टिक एवं पुनर्निर्माण सर्जन डॉ. दुष्यंत जायसवाल और कोलकाता स्थित टाटा मेडिकल सेंटर के वरिष्ठ स्तन कैंसर सर्जन डॉ. संजीत कुमार अग्रवाल ने किया। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान स्तन संरक्षण सर्जरी में ट्यूम र के साथ उसके आसपास के स्वस्थ ऊतक का एक हिस्सा निकालते हुए स्तन के अधिकांश हिस्से को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया दिखाई गई। इसमें कैंसर सर्जरी के साथ प्लास्टिक सर्जरी की तकनीकों का भी उपयोग किया गया, जिससे बचे हुए स्तन ऊतक को व्यवस्थित कर उसके आकार और स्वरूप को बनाए रखने में मदद मिलती है। इसका का उद्देश्य आधुनिक सर्जिकल तकनीकों को साझा करने के साथ चिकित्सकों के बीच अनुभव और ज्ञान का आदान-प्रदान करना था। इस दौरान सर्जिकल योजना, उपचार के विकल्पों और मरीज-केंद्रित निर्णयों पर भी चर्चा हुई। भारत में स्तन कैंसर के बढ़ते मामलों पर डॉ. शलाका जोशी ने कहा, स्तन कैंसर आज दुनिया और भारत में महिलाओं में सबसे अधिक पाए जाने वाले कैंसरों में शामिल है। भारत में इस बीमारी से जूझ रही कई महिलाएँ देर से उपचार के लिए पहुँचती हैं, जिससे उपचार अधिक जटिल और परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए जागरूकता, शुरुआती पहचान, सही निदान, उचित उपचार और पुनर्वास तक देखभाल की निरंतरता जरूरी है। मरीजों के आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की क्षमता को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है। बीएमसी छत्तीसगढ़ कैंसर कॉन्क्लेव जैसे मंच चिकित्सकों को आधुनिक तकनीकों को देखने, जटिल मामलों पर चर्चा करने और अपने अनुभव साझा करने का अवसर देते हैं। लाइव सर्जिकल डेमोन्स्ट्रेशन में स्तन पुनर्निर्माण की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। बालको मेडिकल सेंटर की कंसल्टेंट, प्लास्टिक, पुनर्निर्माण एवं एस्थेटिक सर्जन डॉ. इशिता कात्याल ने कहा, कैंसर उपचार का उद्देश्य केवल बीमारी को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि मरीज के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना भी है। स्तन पुनर्निर्माण इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा प्रयास स्तन के प्राकृतिक स्वरूप और संतुलन को यथासंभव बनाए रखना है, ताकि मरीज आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बीएमसी में स्तन स्वास्थ्य क्लिनिक का शुभारंभ किया। यह पहल क्षेत्र में व्यापक स्तन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के बीएमसी के प्रयासों का हिस्सा है। महिला विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के नेतृत्व में संचालित यह क्लिनिक विभिन्न विशेषज्ञताओं को एक साथ लाकर स्तन स्वास्थ्य प्रबंधन, कैंसर उपचार, स्तन पुनर्निर्माण और कॉस्मेटिक ब्रेस्ट सर्जरी की सभी सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा। इसके बारे में सर्जन आरती सरीन (सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल), पूर्व महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएँ ने कहा, कैंसर उपचार में शुरुआती पहचान और समय पर उपचार महत्वपूर्ण है। व्यापक स्तन स्वास्थ्य क्लिनिक इस क्षेत्र में स्तन स्वास्थ्य से जुड़ी संपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें कैंसर की रोकथाम, नियमित जाँच, शुरुआती निदान, समय पर उपचार और पुनर्निर्माण के साथ पोषण, फिजियोथेरेपी और लिम्फेडेमा प्रबंधन जैसी सहायक सेवाएँ भी शामिल होंगी। इस पर डॉ. भावना सिरोही, मेडिकल डायरेक्टर एवं वरिष्ठ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, बालको मेडिकल सेंटर ने कहा, कैंसर उपचार से जुड़ी विभिन्न विशेषज्ञ सेवाओं को एक साथ लाकर हमारा उद्देश्य मध्य भारत में उपचार की निरंतरता को मजबूत करना और महिलाओं को निदान एवं उपचार से लेकर स्वस्थ होने तक उनकी पूरी उपचार यात्रा में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना है। यह दृष्टिकोण क्षेत्र में अधिक सुलभ और मरीज-केंद्रित कैंसर उपचार व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देगा। चौथा वार्षिक छत्तीसगढ़ कैंसर कॉन्क्लेव क्षेत्र में कैंसर उपचार की विशेषज्ञ क्षमताओं को मजबूत करने, चिकित्सकीय सहयोग और निरंतर सीखने को बढ़ावा देने की बीएमसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश के अग्रणी विशेषज्ञों और क्षेत्रीय चिकित्सकों को एक मंच पर लाकर यह आयोजन मध्य भारत में कैंसर उपचार से जुड़ी जानकारी और अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान कर रहा है।

श्रीकांत बोले, वैभव बनेगा क्रिकेट का अगला स्टारः तीनों ही प्रारुपों में छाने का है दम

चेन्नई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने 15 साल के उभरते हुए क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह विश्व क्रिकेट का अगला बड़ा स्टार बनेगा।

श्रीकांत के अनुसार वैभव में तीनों प्रारुपों में शानदार प्रदर्शन करने का दम है और वे आगे चलकर इस खेल पर राज करेंगे। महज 15 साल की उम्र में, सूर्यवंशी ने अपने असाधारण कौशल और रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन से क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है। श्रीकांत ने सूर्यवंशी के अब तक के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि अगर उन्हें सही तरीके से तैयार किया जाए तो वह विश्व क्रिकेट के लिए एक अमूल्य खिलाड़ी बन सकते हैं। उन्होंने युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, वह बहुत शानदार खेल रहा है। उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर उसे सही ढंग

से तैयार किया जाए, तो वह भविष्य का सुपरस्टार बनेगा। वह टेस्ट क्रिकेट को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाएगा। उसी की वजह से सबने दिलीप ट्रॉफी देखी। आगे चलकर वह वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति साबित होगा।

श्रीकांत ने विश्वास व्यक्त किया कि सूर्यवंशी उच्चतम स्तर पर भी सफल होंगे। उन्होंने कहा कि इस युवा खिलाड़ी में खेल के सभी प्रारूपों में बेहतरीन प्रदर्शन करने की काबिलियत है और उन्होंने विशेष रूप से लाल-गेंद क्रिकेट में गेंदबाजों के खिलाफ उनके निडर स्ट्रोक-प्ले की सराहना की। श्रीकांत का यह समर्थन निश्चित रूप से वैभव सूर्यवंशी के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा, क्योंकि क्रिकेट विशेषज्ञ और प्रशंसक इस युवा प्रतिभा के भविष्य पर करीब से नजर रख रहे हैं। हाल ही में, वैभव सूर्यवंशी ने दिलीप ट्रॉफी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। उन्होंने 15 साल और 157 दिन की उम्र में टूनामेंट के इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया, जिसने 57 साल पुराने एक प्रतिष्ठित रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यह उपलब्धि उनकी प्रतिभा और परिपक्वता का प्रमाण है, जो इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर के टूनामेंट में अपनी छाप छोड़ रहे हैं।

यह रिकॉर्ड बनाने से पहले, नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ ईस्ट जोन की दिलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल जीत में बल्ले से कोई खास कमाल न दिखा पाने के बावजूद, इस 15 वर्षीय खिलाड़ी ने सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल में जबरदस्त वापसी की। सूर्यवंशी ने पहली पारी में 81 गेंदों पर शानदार 92 रन बनाए, जो एक बड़े स्कोर की नींव थी। इसके बाद, उन्होंने आखिरी पारी में अहम 40 रन बनाकर ईस्ट जोन को चार विकेट से जीत दिलाई और फाइनल में जगह पक्की करने में मदद की। दबाव भरे मैचों में उनके इन निर्णायक प्रदर्शनों ने उनकी मानसिक मजबूती और मैच जीतने की क्षमता को दर्शाया है।

महत्वपूर्ण ख़बर

दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज से बाहर हुए एनगिडी की जगह नाकोबानी को शामिल किया

■ केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने 24 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी की जगह पर नाकोबानी मोकोएना को शामिल किया है। वहीं इससे पहले एनगिडी चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो गये। ऐसे में खिलाड़ियों की खराब फिटने से परेशान दक्षिण अफ्रीकी टीम की मुश्किलें और बढ़ गयी हैं। एनगिडी को यह चोट पिछले सप्ताह टाइटन्स और डॉल्फन्सि के बीच खेले गए घरेलू प्रथम श्रेणी मैच के दौरान लगी थी।

कोलंबिया ने मैक्सिको, पराग्वे और पेरु के खिलाफ होने वाले मैत्री फुटबॉल मैचों के लिए नये खिलाड़ियों को शामिल किया

कोलंबिया। कोलंबिया ने इस माह के अंत में मैक्सिको, पराग्वे और पेरु के खिलाफ अमेरिका में होने वाले मैत्री फुटबॉल मैचों के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है। टीम में एक बड़ा बदलाव करते हुए सभी नये खिलाड़ियों को शामिल है। लिवरपूल के स्टार विंगर लुइस डियाज को भी टीम में जगह नहीं दी है। टीम में 11 ऐसे खिलाड़ियों को अवसर मिला है जिन्होंने अभी तक अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं। टीम में पूर्व कप्तान जेम्स रोड्रिगेज तक को जगह नहीं मिली है। रोड्रिगेज ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया था।

नए खिलाड़ियों में बर्मिंघम सिटी के मिडफील्डर जॉन सोलिस और जेनिट सेंट पीटर्सबर्ग के डिफेंडर केविन एंड्रेड शामिल हैं। इनके अलावा, गोलकीपर एल्डेयर क्विंटाना, डिफेंडर रोजर कैसेडो, मिडफील्डर डेनियल आर्किला और फॉरवर्ड कैमिलो डुरान को भी टीम में जगह मिली है। मैनेजर नेस्टर लोरेंजो ने स्थानीय क्लब एटलेटिको नेशनल से लेफ्ट-बैक सैमुअल वेलास्केज और मिडफील्डर जुआन मैनुअल रेंगिफो को भी टीम में शमिल किया है।

बोगोटा में टीम घोषणा के दौरान मैनेजर नेस्टर लोरेंजो ने अपनी चयन नीति को लेकर कहा, कोई भी खिलाड़ी हमेशा टीम में नहीं रहता और न ही हमेशा बाहर रहता है। चाहे वे युवा हों या अनुभवी, इस प्रक्रिया का हिस्सा रहे सभी लोग जानते हैं कि उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए मुकाबला करना होगा, और कोई भी टीम में आ सकता है या बाहर हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लुइस डियाज के मामले में, आपसी सहमति से उन्हें इस समय आराम देने का निर्णय लिया गया है। लोरेंजो ने बताया कि यह कदम युवा प्रतिभाओं को अवसर देते हुए उन्हें अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्रदान करने का भी मौका देने के लिए उठाया गया है। वे 2030 विश्व कप क्वालीफायर से पहले नए खिलाड़ियों को परखने के लिए इन मैत्री मैचों का सहारा लेंगे।

वहीं टीम के पूर्व कप्तान जेम्स रोड्रिगेज के संन्यास पर लोरेंजो ने कहा कि उन्होंने उनके फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हुए उनके फैसले का सम्मान किया है। रोड्रिगेज कोलंबिया के लिए 131 अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। गौरतलब है कि कोलंबियाई टीम कैफेटेरोस का सामना 26 सितंबर को बाल्टीमोर में मेक्सिको से, 2 अक्टूबर को न्यू जर्सी में पैराग्वे से और 6 अक्टूबर को मियामी में पेरू से होगा। ये मैच जुलाई में हुए विश्वकप के राउंड ऑफ 16 में स्विट्जरलैंड से पेनल्टी शूटआउट में हारने के बाद टीम के पहले मुकाबले होंगे, और ये युवा खिलाड़ियों के लिए अपने को साबित करने का मंच उपलब्ध करायेंगे।

डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक समय छाये रहे थे 235 किलो के रेसलर आंद्रे जायंट

सेन डियागो। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (डब्ल्यूडब्ल्यूई) की दुनिया अपने विशालकाय रेसलर्स और अतरंगी कहानियों के लिए जानी जाती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा से अपने प्रशंसकों के लिए कुछ न कुछ नया पेश करता रहा है, इसमें अजीब किरदार वाले रेसलर भी आकर्षण का केन्द्र रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक ऐसे ही एक अकल्पनीय रेसलर थे आंद्रे द जायंट, जो करीब 7 फीट से अधिक लंबे और लगभग 235 किलो वजनी थे। जब रिंग में उतरते थे, तो सामान्य कद-काठी के रेसलर उनके सामने बच्चे प्रतीत होते थे। उनका जीवन कई अविश्वसनीय किस्सों से भरा है। वह अपने करियर में शुरूआत 15 साल में कभी कोई मुकाबला नहीं हारे। आंद्रे का जन्म फ्रांस के ग्रेनोबल में आंद्रे रेने रुसिमॉफ के नाम से हुआ था। उनके परिवार के अन्य सदस्य सामान्य थे, लेकिन आंद्रे का शरीर बचपन से ही असामान्य रूप से बढ़ता चला गया। उनकी इस असाधारण लंबाई और भारी-भरकम शरीर का कारण एक्रोमेगाली नामक एक दुर्लभ बीमारी थी, जिसमें शरीर का विकास हार्मोन अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। बड़े होने पर उनका कद 7 फीट 4 इंच और वजन 235 किलो तक पहुंच गया, जिसके चलते उन्हें बचपन से ही सामान्य जीवन जीने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आंद्रे को एक नई पहचान दी। इसमें बड़ी कद काठी वाले रेसलरों की खूब मांग थी, और कंपनी के मालिक विंस मैकमोहन ने आंद्रे की क्षमता को पहचाना। 1970 और 1980 के दशक में वह कंपनी के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गए। अपने करियर के शुरूआती 15 सालों तक उन्हें किसी भी मैच में पिनफॉल या सबमिशन के जरिए कभी हराया नहीं गया, जो कुश्ती इतिहास का एक गौरवपूर्ण रिकॉर्ड है।

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलना चाहते हैं राउफ

बोले, लंबे प्रारूप को लेकर बदल गया है नजरिया

लाहौर। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने कहा है कि वह अवसर मिलने पर श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में खेलने के लिए तैयार हैं। रऊफ के इस बयान से सभी हैरान हैं क्योंकि एक समय उन्होंने टेस्ट प्रारुप खेलने से इंकार तक कर दिया था। वहीं अब वह इस प्रारुप में वापसी करना चाहते हैं। इसका कारण राष्ट्रीय टीम में सीमित ओवरों के क्रिकेट में घटते अवसरों और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की नई कठोर नीति को माना जा रहा है। इससे ये गेंदबाज अब लंबे प्रारुप में भी खेलने को तैयार है। इस कारण अब वह घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेल रहे हैं। उनका पहला लक्ष्य नवंबर में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम में जगह बनाना है।

अभी रऊफ पाकिस्तान में खेली जा रही प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में पाकिस्तान टेलीविजन की ओर से सक्रिय हैं। इस टूनार्मेंट में हाल ही में उन्होंने ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए पांच महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। भले ही वह मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ पर रऊफ का यह प्रभावशाली स्पैल चयनकताओं की नजरों में आने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। मौजूदा जानकारी के अनुसार, रऊफ का स्पष्ट इरादा है कि प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन चयनकताओं का ध्यान खींचे।

यह बदलाव कई मायनों में आश्चर्यजनक है, क्योंकि कुछ साल पहले तक रऊफ का टेस्ट क्रिकेट को लेकर बिल्कुल अलग रुख था। पाकिस्तान में लगातार मांग उठने के बावजूद कि वह लंबे प्रारूप में देश का प्रतिनिधित्व करें, वे इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उत्सुक नहीं दिखे। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई साल बिताने के बावजूद, उन्होंने अब तक सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है, जो लगभग चार साल पहले हुआ था। हाल के महीनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके संबंध भी बहुत सहज नहीं रहे हैं, और वह मुख्य रूप से एकदिवसीय क्रिकेट तक ही सीमित रहे हैं, उनका आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच लगभग एक साल पहले भारत के खिलाफ एशिया कप फाइनल में था।

अब रऊफ ने खुद यह बात स्वीकार की है कि उन्होंने लंबे प्रारूप को लेकर अपना नजरिया बदला है। उनका मानना है कि पाकिस्तान को तेज गेंदबाजों की सख्त जरूरत है और प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में उनके पास अभी खुद को साबित करने के लिए कई मुकाबले बाकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पिछले सीजन में चार दिवसीय क्रिकेट खेली थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज से पहले भी दूसरे स्तर की घरेलू क्रिकेट में समय बिताया था, जिसे वे खुद को एक बेहतर गेंदबाज बनाने का अच्छा तरीका मानते हैं।

रऊफ के इस बदलाव में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालिया सख्ती का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बोर्ड ने राष्ट्रीय टीम से बाहर रहने वाले खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेना अनिवार्य कर दिया है, ऐसा न करने पर खिलाड़ियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसी नीति के बीच, कई प्रमुख पाकिस्तानी खिलाड़ियों का घरेलू क्रिकेट की ओर लौटना देखा गया है, जिसमें तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में लाल गेंद के खेल को प्राथमिकता देने की बात कही है। हालांकि, हारिस रऊफ के लिए श्रीलंका सीरीज में जगह बनाना आसान नहीं होगा। उन्हें प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी के शेष मुकाबलों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा, अपनी फिटनेस और लंबे प्रारूप की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता साबित करनी होगी।

कारोबार

ट्रंप टैरिफ के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत

मूडीज ने जीडीपी अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% किया, महंगाई का खतरा

नई दिल्ली। मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक निजी खपत, सरकारी बुनियादी ढांचा खर्च और सेवा क्षेत्र की मजबूती से अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है। हालांकि पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा खिंचने पर तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और महंगाई 4.8% के अनुमान से ऊपर जा सकती है। जेफरीज ने 11-12% सांकेतिक वृद्धि का अनुमान जताया है।

पश्चिम एशिया के गहराते संघर्ष और अमेरिकी टैरिफ के आसन्न संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है। मूडीज रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। हालांकि, रेटिंग एजेंसी ने चेतावनी दी है कि तेल की ऊंची कीमतों और अल नीनो के प्रभाव से महंगाई का जोखिम अभी भी बना हुआ है।

मूडीज ने कहा कि कैलेंडर वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में भारत की वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि सालाना आधार पर बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गई, जो समूचे कैलेंडर वर्ष 2025 की 7.3 प्रतिशत वृद्धि से अधिक है। इसमें निजी खपत में मजबूती, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर लगातार खर्च से सकल स्थिर पूंजी निर्माण में मजबूत वृद्धि और निजी क्षेत्र के निवेश में संभावित सुधार के साथ सेवा क्षेत्र की लगातार मजबूती का योगदान रहा। भारत की ह्यबीएए3ह्ल रेटिंग की समीक्षा के बाद मूडीज अनुमान है कि भारत पर कर्ज का बोझ लगातार अधिक बना हुआ है। ब्याज लागत भी ऊंचे स्तर पर है, जो बड़ा जोखिम है।

4.8 फीसदी से ऊपर जा सकती है महंगाई

रेटिंग एजेंसी ने कहा, भविष्य में यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष का स्थायी समाधान नहीं होता है तो ऊर्जा की ऊंची कीमतें चालू वित्त वर्ष में सालाना औसत महंगाई को 4.8 प्रतिशत के अनुमान से ऊपर ले जा सकती हैं। यह वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 2.4 प्रतिशत के मुकाबले काफी अधिक है।

12% तक की सांकेतिक वृद्धि हासिल करेगा भारतः जेफरीज

पूंजी बाजार फर्म जेफरीज के अनुसार, मजबूत घरेलू मांग, बैंक क्रेडिट में तेजी और आर्थिक गतिविधियों में सुधार के दम पर भारत चालू वित्त वर्ष में 11 से 12 फीसदी की सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर्ज करने की राह पर है। इसका मतलब है कि बड़े आर्थिक आधार मजबूत बने हुए हैं।

अमेरिका-सऊदी के बीच दो लाख करोड़ की डील

एफ-35 लड़ाकू विमान समेत और क्या बेचने की तैयारी?

वॉशिंगटन, एजेंसी

हूतियों के बढ़ते हमलों के बीच अमेरिका ने सऊदी अरब को 48 एफ-35 लड़ाकू विमान बेचने का रास्ता साफ कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 24.3 अरब डॉलर (लगभग 2 लाख करोड़ रुपये) की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब रियाद हूतियों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए वॉशिंगटन से सैन्य मदद मांग रहा था।

अमेरिका ने हालांकि, सऊदी अरब के आग्रह के बावजूद हूतियों के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई से इन्कार किया। इसके बजाय वॉशिंगटन ने रियाद को खुफिया जानकारी और टारगेटिंग सहायता देने की बात कही। इसी बीच हूतियों ने सऊदी शहरों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर दबाव बढ़ाया। ऐसे

माहौल में सऊदी अरब की अपनी हवाई रक्षा क्षमता मजबूत करने की जरूरत और बढ़ी। इसी क्रम में एफ-35 सौदा सामने आया है।

अमेरिका से क्या-क्या खरीदेगा सऊदी अरब

अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक प्रस्तावित पैकेज में 48 एफ-35 विमान, 49 प्रैट एंड व्हिटनी एफ135 इंजन, सुरक्षित संचार और नेविगेशन उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सहायता, स्पेयर पार्ट्स, प्रशिक्षण, सिम्युलेटर, सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल हैं।

घटनाक्रम को एक साथ देखें तो हूतियों के खिलाफ प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप से पीछे हटने के बाद अमेरिका ने सऊदी को अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक अमेरिकी हथियारों का विकल्प दिया है। 24.3 अरब डॉलर का सौदा वॉशिंगटन की रणनीति से मेल खाता है।

ड्रोन हमले से सऊदी की पाइपलाइन ठप

सऊदी। सऊदी अरामको ने कम से कम दो यूरोपीय रिफाइनिंग ग्राहकों को अक्तूबर में कच्चे तेल की डिलीवरी नहीं देने की जानकारी दी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, यह फैसला ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमले के बाद लिया गया, जिसमें तीन पंपिंग स्टेशन क्षतिग्रस्त हुए। पोलैंड की ओर्लेन ने वैकल्पिक रूप से उत्तरी सागर का तेल खरीदा है। अरामको पाइपलाइन को कुछ दिनों में आंशिक और करीब छह सप्ताह में पूरी क्षमता पर लाने की कोशिश कर रही है।

उदय कोटक बोले

विकास के लिए राजकोषीय अनुशासन, सुधार अहम

नई दिल्ली। अनुभवी बैंकर उदय कोटक ने शुक्रवार को 2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल करने के लिए राजकोषीय अनुशासन, अधिक पूंजी और बेहतर विनिर्माण क्षमताओं का आह्वान किया।

उन्होंने वैश्विक तकनीकी कंपनियों के बढ़ते प्रभाव से राष्ट्रीय संप्रभुता और आर्थिक स्वतंत्रता को चुनौती बताया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सम्मेलन में कोटक ने केंद्र-राज्यों के समन्वय को महत्वपूर्ण कहा। भारत को राजकोषीय समेकन, वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और सोने के आयात को संबोधित करने सहित सात प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। कोटक ने बताया कि भारत का समेकित राजकोषीय घाटा 7 फीसदी से अधिक है। उन्होंने आयात पर निर्भरता कम करने और दुनिया को चाहिए ऐसे उत्पाद बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कोटक ने वित्तीय विनियमन और विकास में संतुलन का भी आह्वान किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के लिए नवाचार और रचनात्मक विनाश अपनाने का आग्रह किया।

तेलंगाना ने 20 हजार करोड़ का पैकेज मांगा

तेलंगाना विधानसभा ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। यह पैकेज अल नीनो के प्रभाव से राज्य में हुई बारिश की कमी से निपटने के लिए है। उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने बताया कि 1 जून से 16 सितंबर तक राज्य में केवल 536.6 मिमी बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 664.5 मिमी होती है। राज्य के 33 में से 19 जिले बारिश की कमी से जूझ रहे हैं। मानसून में सामान्य खेती का क्षेत्र 139.29 लाख एकड़ है, लेकिन केवल 88 फीसदी पर ही फसलें उगाई जा सकीं। 15 सितंबर तक प्रमुख जलाशयों में 585 टीएमसी क्षमता के मुकाबले सिर्फ 241 टीएमसी पानी उपलब्ध था, जबकि पिछले साल यह 497 टीएमसी था। यह पानी केवल पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, रबी फसलों के लिए नहीं। प्रस्ताव में पेयजल, सिंचाई और सूखा राहत के लिए 20,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की गई है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऋक्कट उधार सीमा को ऋक्कउद्ध के 3 फीसदी से बढ़ाकर 3.5 फीसदी करने की अपील की गई।

एमपी-यूपी के लिए लाइफलाइन जबलपुर-वाराणसी एक्सप्रेसवे

सतना, रीवा, प्रयागराज तक हाई-स्पीड कनेक्टिविटी का नया रूट तैयार

जबलपुर। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाला जबलपुर-वाराणसी एक्सप्रेसवे महाकौशल से विंध्य और उत्तर प्रदेश तक तेज कनेक्टिविटी देने वाला अहम प्रोजेक्ट होगा।

इसके बनने के बाद जबलपुर से वाराणसी का सफर करीब 5 घंटे में पूरा होने की उम्मीद है। यह कॉरिडोर कटनी, मैहर, सतना, रीवा और प्रयागराज जैसे प्रमुख शहरों को भी बेहतर तरीके से जोड़ेगा।

5 घंटे में पूरा होगा जबलपुर-वाराणसी का सफर

फिलहाल जबलपुर से वाराणसी की दूरी करीब 460 से 480 किलोमीटर है। मौजूदा 2 लेन मार्ग से सफर करने में लगभग 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। नए एक्सप्रेसवे के बनने के बाद 4 लेन हाई-स्पीड रास्ता उपलब्ध होगा। वाहनों की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहने की उम्मीद है। इससे यात्रा के समय में करीब 5 से 6 घंटे की कमी आ सकती है। यानी जबलपुर से वाराणसी का सफर करीब 5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इससे धार्मिक यात्रा करने वाले यात्रियों को भी काफी सुविधा मिलेगी।

ये शहर होंगे सीधे कनेक्ट

जबलपुर-वाराणसी एक्सप्रेसवे के जरिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहर बेहतर तरीके से जुड़ेंगे। इनमें जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा, प्रयागराज और वाराणसी शामिल हैं। यह रूट मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र से शुरू होकर विंध्य क्षेत्र के रास्ते उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल तक पहुंचेगा। कॉरिडोर रीवा-सतना बेल्ट के साथ उत्तर प्रदेश के मिजार्पुर और प्रयागराज के बाहरी हिस्सों को टच करते हुए वाराणसी रिंग रोड से जुड़ेगा।

एमपी-यूपी की नई लाइफलाइन बनेगा कॉरिडोर

जबलपुर-वाराणसी हाई-स्पीड कॉरिडोर को रणनीतिक रूप से तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए महाकौशल, विंध्य और पूर्वांचल के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। व्यापार के साथ धार्मिक पर्यटन को भी इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। जबलपुर सीधे प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ जाएगा।

करीब 30 हजार करोड़ की लागत

जबलपुर-वाराणसी एक्सप्रेसवे वाराणसी-विशाखापट्टनम कॉरिडोर का हिस्सा है। यह आधुनिक, ग्रीनफील्ड और एक्सेस-कंट्रोल हाईवे नेटवर्क का हिस्सा होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 30,000 करोड़ रुपये बताई गई है।

DPR और सर्वे का काम अंतिम दौर में

इस अहम प्रोजेक्ट को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक मंजूरियों और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और तकनीकी दल ने एलाइनमेंट को लेकर शुरूआती सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अहम चुनौती है, क्योंकि एक्सप्रेसवे दोनों राज्यों के कई जिलों से होकर गुजरेगा। माना जा रहा है कि अगले साल तक इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो सकती है।

इंदौर से सीधे कनेक्ट होगा बुदनी

रेलवे स्टेशन को जंक्शन के रूप में मिलेगी पहचान

इंदौर। इंदौर से रेल रूट से बुदनी और नर्मदापुरम की सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे यात्रा में समय भी बचेगा। बुदनी रेलवे स्टेशन आने वो समय में जंक्शन के रूप में लेने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इटारसी और भोपाल के बीच यह बड़ा जंक्शन होगा।

बुदनी स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही इससे यात्रा में लगने वाला लंबा समय भी कम होगा। इस स्टेशन पर पहले कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज था, अब जंक्शन बनने के बाद इसमें कई ट्रेनों का स्टॉपेज रहेगा। इससे इस क्षेत्र के यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

बुदनी रेलवे स्टेशन पर नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। जल्द ही यह बनकर तैयार हो जाएगी। जिस रेलवे स्टेशन पर तीन दिशाओं की ओर से ट्रेन आती है उसे जंक्शन कहा जाता है। ऐसे में आने वाले समय में बुदनी रेलवे स्टेशन भोपाल और इटारसी के बीच महत्वपूर्ण रहेगा।

सलकनपुर मार्ग से जुड़ेगा जुड़ेगा क्षेत्र

बुदनी रेलवे स्टेशन के जंक्शन बनने से तीसरी लाइन मिलेगी। इसके साथ ही सलकनपुर मार्ग भी इससे जुड़ जाएगा। इस नए रूट के बनने से अब ट्रेनों को भोपाल घूमकर नहीं जाना होगा। इससे यात्रियों का समय बचेगा।

बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह सम्पन्न

ज्ञान, प्रतिभा और संकल्प से युवा विकसित भारत के निर्माण में दें योगदान: राज्यपाल

भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि युवाओं को अपनी शिक्षा और प्रतिभा का उपयोग व्यक्तिगत सफलता के साथ समाज, पर्यावरण और राष्ट्र के हित में करना चाहिए। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और जनसेवा की भावना महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखने तथा माता-पिता, शिक्षकों और समाज के योगदान का सदैव स्मरण रखने का आह्वान किया।

राज्यपाल श्री पटेल ने यह बात बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही। दीक्षांत कार्यक्रम का

आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को किया गया।

राज्यपाल श्री पटेल ने महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद् बरकतउल्लाह जी के देश प्रेम तथा अपनी माटी की सेवा के जज्बे का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत, अनुशासन और लगन का उत्सव है, जो उनके जीवन में नई जिम्मेदारियों और अवसरों के द्वार खोलता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी की यात्रा अलग होती है। उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ माता-पिता के त्याग और शिक्षकों के सहयोग के लिए सदैव आभारी रहना चाहिए। वे जहाँ भी जाएँ, अपने विश्वविद्यालय और परिवार की गरिमा बढ़ाने का प्रयास करें। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा व्यवस्था का केवल सूचना और ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं रही, बल्कि सत्य की खोज, चरित्र निर्माण और लोक कल्याण का मार्ग रही है। गुरु-शिष्य परंपरा में समानता, अनुशासन और चरित्र निर्माण को महत्व दिया गया। श्रीकृष्ण, बलराम और सुदामा का गुरु सांदीपनि के आश्रम में समान शिक्षा प्राप्त करने का प्रसंग इसका प्रेरक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को वर्तमान चुनौतियों के समाधान और भविष्य के नवाचार का माध्यम बनाना होगा।

राज्यपाल श्री पटेल ने दीक्षांत समारोह की थीम ह्यहरित ऊर्जा से विकसित भारत बनाने की पहलह्न की सराहना की, कहा कि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी आवश्यक है। प्रकृति के निरंतर दोहन से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियां सामने आई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के ह्यएक पेड़ माँ के नामह्न अभियान का उल्लेख किया।

दमोह में खूनी वारदात

पति ने पत्नी और तीन मासूम बच्चों को कुल्हाड़ी से काटकर पूरे परिवार को मार डाला

दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मगरोन थाना अंतर्गत ग्राम कबीरपुर में शनिवार की सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई।

एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सहित तीन बच्चों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

सोते समय कुल्हाड़ी से किया हमला

पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी ने बताया कि शनिवार सुबह लगभग 4 बजे द्वारका पटेल पुत्र कल्लू पटेल उम्र 28 वर्ष ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी खेमा पटेल 25 वर्ष, पुत्री उर्मिला पटेल 7 वर्ष, पुत्र उमेश 4 वर्ष और राजा 1 वर्ष की सोते समय हत्या कर दी।

साल भर से चल रहा था पारिवारिक विवाद

हत्या के मामले में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच काफी लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। एक वर्ष पूर्व पत्नी खेमाबाई ने मगरोन थाने में पति के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था। उसके बाद भी दोनों के बीच आपसी कलह बनी हुई थी। शुक्रवार को भी दोनों के बीच विवाद होने पर आरोपी द्वारका पटेल के ससुर ने आकर दोनों को समझाकर मामला शांत कराया था। लेकिन उनके जाने के बाद रात में फिर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ। उसके बाद सुबह पति ने चारों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी।

आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पारिवारिक कलह किस बात को लेकर चल रही थी, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। घटना की जानकारी लगते ही घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी के अलावा अन्य अधिकारी और ञ्रछ की टीम भी पहुंच गई है।

जाति प्रमाणपत्र से संबंधित शिकायत पर सतर्कता शाखा की कार्रवाई

भोपाल। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तुत होकर आरक्षित वर्ग का लाभ प्राप्त करने तथा जाति प्रमाणपत्र से संबंधित शिकायत पर पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा द्वारा कार्रवाई की गई है। शिकायत की जांच एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर थाना सतर्कता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल में संबंधित निवृतमान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है। यह प्रकरण आवेदक श्री हरवीर सिंह रघुवंशी, निवासी राघौगढ़, जिला गुना द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर पंजीबद्ध किया गया है।

प्रकरण से संबंधित जाति प्रमाणपत्र की जांच मध्यप्रदेश शासन की ह्लअनुसूचित जनजाति संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समितिह्व, भोपाल द्वारा की गई थी। समिति द्वारा उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों की जांच के उपरांत क्षेत्र संयोजक, आदिम जाति कल्याण, विदिशा द्वारा वर्ष 1984 में जारी अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र को अमान्य घोषित किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है।

कूनो फिर हुआ गुलजार, मादा चीता केजीपी 12 के परिवार में आए चार नन्हे शावक

प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल से शुरू हुई चीता पुनर्स्थापना यात्रा में कूनो ने रचा नया अध्याय

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जीवन अपना रास्ता खुद ढूंढ ही लेता है और जीवन की यही प्रकृति इसे और भी अधिक रोमांचक बनाती है। एक वक्त था, जब मध्यप्रदेश में गिनती के चीते हुआ करते थे। आज यहां चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अत्यंत हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 17 सितंबर 2022 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुई चीता पुनर्स्थापना की ऐतिहासिक यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि कूनों में बीते दिनों जन्मे चार नन्हें शावक चीता संरक्षण की हमारी यात्रा में आशा, जीवटता और सफलता का सुंदर प्रतीक है। पुनर्स्थापना के चार वर्ष पूर्ण होने के अगले ही दिन शुक्रवार (18 सितम्बर को) भारत में ही जन्मी मादा चीता केजीपी12 ने कूनों में चार नन्हें शावकों को जन्म दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के लिये यह ऐतिहासिक और हर्ष का क्षण है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न

केवल देश में चीतों की संख्या बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह भी दशार्ती है कि कूनो का प्राकृतिक वातावरण चीतों के प्रजनन और उनके संरक्षण के लिए अनुकूल बन रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चीता प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है।

प्रोजेक्ट चीता : 56 हुआ भारत में चीतों का कुनबा

प्रमुख तथ्य

- कूनो में गूंजी चीतों की नई किलकारी - भारत में जन्मी मादा ङञ्रढ्ढ12 ने 4 शावकों को दिया जन्म, 52 से बढ़कर 56 हुआ भारत में चीतों का कुनबा।
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रोजेक्ट चीता के संरक्षण, संवर्धन और इनकी सुरक्षा पर हो रहा है निरंतर ठोस कार्य।
- भारत में जन्मी मादा चीता ङञ्रढ्ढ12 ने दिया 4 शावकों को जन्म। नई आमद के साथ चीता संख्या 52 से बढ़कर 56 हो गई है।
- चार वर्ष - चार नई जिंदगियां। प्रोजेक्ट चीता की यात्रा में यह उपलब्धि भारत में चीता संरक्षण और प्राकृतिक प्रजनन की सफलता का महत्वपूर्ण प्रतीक है। मध्यप्रदेश चीतों के संरक्षण का मजबूत केंद्र बन गया है।

वर्ष 2022 से 2026 तक चीता पुनर्स्थापना का सफल सफर

- 17 सितंबर 2022 - नामीबिया से 8 चीते कूनो पहुंचे।
- फरवरी 2023 - दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए गए।
- फरवरी 2026 - बोत्सवाना से 9 चीते भारत लाए गए।
- इन पुनर्स्थापना प्रयासों और भारत में हुए प्रजनन के परिणामस्वरूप अब कुल 56 जीवित चीते हैं।
- 52 से 56 - चीता परिवार में चार नए सदस्य
- चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत में 52 जीवित चीते थे।
- केजीपी 12 द्वारा 18 सितम्बर 2026 को चार शावकों को जन्म देने के बाद अब संख्या 56 हो गई है। भारत में जन्मे चीतों की संख्या अब 36 हो गई है। नए शावकों के साथ भारत में जन्मी चीता पीढ़ी का विस्तार और मजबूत हुआ है।

मध्यप्रदेश में चीता संरक्षण का हो रहा विस्तार

- वर्तमान में मध्यप्रदेश प्रोजेक्ट चीता का प्रमुख केंद्र है।
- कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 49 चीते और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में 3 चीते थे।
- चार नए शावकों के जन्म के बाद कूनो में चीतों की संख्या 53 और मध्यप्रदेश में कुल चीता संख्या 56 हो गई है।
- कूनो के साथ गांधी सागर में भी चीता संरक्षण का सफल विस्तार किया गया है।

पुनर्स्थापना से प्रजनन तक

- 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के साथ भारत में प्रोजेक्ट चीता की शुरूआत हुई थी।
- इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते भारत लाए गए।
- भारत में हुआ चीतों का प्रजनन। भारत में जन्मी मादा द्वारा चार शावकों को जन्म देना इस यात्रा में नई उपलब्धि है।
- भारत में चीता संरक्षण पुर्नस्थापना तक ही सीमित नहीं, अब यह प्रजनन और नई पीढ़ी के संरक्षण के चरण में पहुंच चुका है।

नलखेड़ा में बगलामुखी मंदिर के पास नाले में बही कार, ओडिशा से आए 8 श्रद्धालुओं की मौत

आगर-मालवा। आगर-मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के पास बीती रात मूसलधार बारिश के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया।

तेज बारिश के बीच पानी के तेज बहाव में एक कार नाले में बह गई। हादसे में कार सवार 3 बच्चों, 3 पुरुषों और 2 महिलाओं सहित कुल 8 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है।

बताया जा रहा है कि बीती रात क्षेत्र में तेज बारिश हो रही थी। इसी

दौरान श्रद्धालुओं से भरी कार नाले में पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई और बह गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए कार और शवों को नाले से बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस घटना की परिस्थितियों और हादसे के कारणों की जांच में जुटी है।

रस्सी से खींचकर कार को किनारे पर लाए

देर रात घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। सुबह स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी से खींचकर कार को नाले के किनारे पर लाया गया। इसके बाद उसमें सवार लोगों के शव बाहर निकाले गए।

ओडिशा के श्रद्धालु बताए जा रहे हैं

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये सभी ओडिशा से उज्जैन दर्शन करने पहुंचे थे। इसके बाद सभी नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन करने आए थे। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस गाड़ी के नंबर से वाहन मालिक की जानकारी ले रही है। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई है। बताया जा रहा है कि कार देर रात को नाले में गिरी थी। हादसे के वक्त नाले में पानी उफान पर था। इस वजह से किसी को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला।

सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश के लिए मध्यप्रदेश में अपार संभावनाएं : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली के यशोभूमि स्थित सेमीकॉन इंडिया 2026 में मध्यप्रदेश पवेलियन का भ्रमण कर सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने मध्यप्रदेश में निवेश, तकनीकी सहयोग और सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विस्तार की संभावनाओं पर उद्योग प्रतिनिधियों से चर्चा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। सेमीकंडक्टर, चिप डिजाइनिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार उद्योगों को आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने पारस सेमीकंडक्टर्स, थॉमसन सेमीकंडक्टर्स, स्प्रिन्टोनिक्स एआई, एनएक्सपी इंडिया, मार्वल सेमीकंडक्टर्स, एल एंड टी सेमीकंडक्टर्स और स्वदेश आईसी सेमीकंडक्टर्स सहित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से संवाद किया।

वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा

मुख्यमंत्री ने इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रुप (आईएसआईजी) के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में जापान की एक्रेटेक, केनन और कैइजो, कोरिया की हनवा और जेनसेम इंक तथा अमेरिका की मेकडरमिड अल्फा के प्रतिनिधि शामिल थे। जापानी प्रतिनिधिमंडल में आक्साईड कार्पोरेशन, स्केल फोटोनिक्स और इम्प्यूट इंक के प्रतिनिधियों से भी चर्चा हुई।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।